डाक विभाग की वार्षिक समीक्षा बैठक में 16 प्रतिशत राजस्व वृद्धि दर्ज, राजस्थान सर्किल रहा अव्वल।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
एक्शन इंडिया
वर्षः 20 अंकः 111 पृष्ठः 12
RNI : DELHIN/2006/19302
actionindianews@gmail.com
राष्ट्रीय संस्करण
दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड - चंडीगढ़
RKB GROUP Rakesh Bhardwaj Group

जम्मू के उधमपुर में सड़क हादसा, 21 की मौत, यात्री बोले- तेज रफ्तार बस का टायर फटा, ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका

टीम एक्शन इंडिया

उधमपुरः जम्मू के उधमपुर में सोमवार सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई। रामनगर से आ रही बस कगोत के पास सड़क से करीब 100 मीटर नीचे गिरकर पलट गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 से ज्यादा यात्री घायल हो गए।

हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। बस में 50 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर लोग रामनगर से उधमपुर में अपने रोजाना के काम पर जा रहे थे। 15 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाकी 6 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों के मुताबिक बस ओवरलोड थी, रफ्तार भी तेज थी। कगोत नाले के पास अचानक बस का टायर फट गया। इससे ड्राइवर उसे कंट्रोल नहीं कर सका। और बस सड़क से नीचे गिर गई। हादसे में बस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर बताया कि हादसे का शिकार हुई बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थी। घायलों का इलाज ऊधमपुर में किया जा रहा है। इधर, पीएम मोदी ने हादसे में

मरने वाले लोगों के लिए संवेदना जताई और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे वाली जगह पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे की वजह बस का ओवरलोड और तेज रफ्तार होना था। घायल यात्रियों से पूछा गया तो वे बोले कि ड्राइवर बहुत तेज बस चला रहा था। बस का टायर फटने से वह स्पीड कंट्रोल नहीं कर सका। जिसके कारण वह करीब 100 मीटर की ऊंचाई से गिर गई।

दर्दनाक हादसा

देश जानता है, हर चुनौती का सामना करने के लिए भाजपा ईमानदारी से कोशिश कर रही है : मोदी

बस की चपेट में ऑटो भी आया

बस नीचे सड़क पर उलटी गिरने से पहले एक ऑटो-रिक्शा को कुचलती हुई गई। अधिकारियों ने बताया कि ऑटो-रिक्शा में सवार लोगों को चोटें आईं, लेकिन वे बच गए।

हादसे के बाद उसी रास्ते से गुजर रहे सेना के एक काफिले ने बचाव अभियान की कमान संभाली। बाद में एक हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से गाड़ी को सीधा किया गया।

चिप्स से लेकर शिप्स तक, भारत-कोरिया मिलकर नए अवसर साकार करेंगे: मोदी

भारत-दक्षिण कोरिया आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को अधिक प्रगाढ़ करते हुए आपसी व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक ले जाने को लेकर समहत हुए हैं : विदेश मंत्रालय

सार्थक चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने नई दिल्ली में सार्थक और व्यापक बातचीत की

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को नई दिशा मिली है। भारत और दक्षिण कोरिया आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को अधिक प्रगाढ़ करते हुए आपसी व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक ले जाने को लेकर समहत हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने नई दिल्ली में सार्थक और व्यापक बातचीत की।

बातचीत के बाद दोनों नेता कई समझौतों और व्यवस्था के आदान-प्रदान के साक्षी बने।

वार्ता में दोनों नेताओं ने भारत-दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई कुल प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, वित्तीय सेवाओं, जहाज निर्माण, एआई, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, रक्षा और सुरक्षा, साथ ही लोगों के बीच और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत-दक्षिण कोरिया स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत संयुक्त दृष्टि पत्र, शिपबिल्डिंग, समुद्री लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास पर अहम समझौते हुए। साथ ही, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को उन्नत करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की घोषणा की गई। दोनों देशों ने पोट्र्स, स्टील सप्लाई चेन, एमएसएमई, विज्ञान-प्रौद्योगिकी और डिजिटल ब्रिज जैसे क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वित्तीय सहयोग के तहत एनपीसीआई और कोरियाई संस्थान के बीच भुगतान प्रणाली को लेकर समझौता हुआ। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, पेरिस समझौते के तहत सहयोग और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2026-2030), खेल और रचनात्मक उद्योगों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा संवाद शुरू करने, इंडो-पैसिफिक पहल में कोरिया की भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने जैसे कदमों की घोषणा की। वर्ष 2028-29 को भारत-कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्वी क्षेत्र) पी. कुमारन ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग की भारत यात्रा के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली ने हैदराबाद हाउस में सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूपों में व्यापक और सार्थक चर्चा की। कुमारन ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि खाड़ी संकट के मुद्दे पर समस्या के समाधान को लेकर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई।

भारत प्राचीन और समकालीन, दोनों तरह की कहानियों का खजानाः दक्षिण कोरिया

चर्चा खाड़ी संकट के प्रभावों को समझने और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, रसायन बाजार, ईंधन बाजार और उर्वरक बाजार में होने वाली बाधाओं के संदर्भ में प्रभावों से कैसे निपटा जाए—इस पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा, भारत प्राचीन और समकालीन, दोनों तरह की कहानियों का खजाना है, जिन पर गेम्स बनाए जा सकते हैं। इनमें कोरियाई टेक्नोलॉजी और स्पेशल इफेक्ट्स की क्षमताओं का लाभ उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया को वेव्स इवेंट के अगले संस्करण में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। एक विशेष पहल के तौर पर राष्ट्रपति ली ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति जे-म्यूंग ली ने ह्यभारत-कोरिया व्यापारिक नेताओं के संवाद में व्यापार जगत के नेताओं के साथ बातचीत की।

नेशनल हेराल्ड केस, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली

नई दिल्लीः नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। ट्रायल कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर को सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच कर रही है।

सऊदी अरब दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल ने द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय स्थिति पर की चर्चा।

मंत्रालय ने देशभर में चल रही प्रमुख ग्रामीण कल्याण और आधारभूत ढांचा योजनाओं की समीक्षा की

ग्रामीण योजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने में जुटी सरकार

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और उसके कारण वैश्विक सप्लाई चेन, वस्तुओं की कीमतों तथा महंगाई पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देशभर में चल रही प्रमुख ग्रामीण कल्याण और आधारभूत ढांचा योजनाओं की समीक्षा की है। मंत्रालय ग्रामीण रोजगार, आवास निर्माण, सड़क विकास और जल संरक्षण योजनाओं पर संभावित असर की लगातार निगरानी कर रहा है। लाभार्थियों को समय पर सहायता मिले, फंड की उपलब्धता बनी रहे और योजनाओं का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

सोमवार को इंटर मिनिस्टीरियल पत्रकार वार्ता में ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला ने बताया रोजगार और मजदूरी सुरक्षा महात्मा गांधी राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 प्रस्तावित वीबी-जी राम जी एक्ट, 2025 लागू होने तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा। ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में कोई बाधा नहीं आएगी। मनरेगा के तहत मांग पर रोजगार देने, समय पर मजदूरी भुगतान सहित सभी कानूनी अधिकार पहले की तरह जारी रहेंगे। तय वर्तमान मजदूरी दरें लागू रहेंगी। मजदूरी भुगतान समय पर हो, इसके लिए लगभग 17,744 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि नया कानून लागू होने पर 125 दिनों के रोजगार की बेहतर गारंटी दिए जाने का प्रस्ताव है। संशोधित मजदूरी दरें अलग से घोषित की जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति या कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना को देखते हुए समय पर डीबीटी भुगतान, आवास सोफ्ट से निगरानी, जियो-टैगिंग और अधूरे घरों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।

नासिक टीसीएसः टीम लीडर गलत तरीके से छूता था':

नासिकः मुंबई के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में काम करने वाली एक महिला इंजीनियर ने अपने साथ हुए उत्पीड़न का खुलासा किया है। महिला का दावा है कि ऑफिस में हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की जाती थीं। इंजीनियर के मुताबिक, ट्रेनिंग सेशन के दौरान टीम लीडर उसे गलत तरीके से छूता था। उसके साथ ऑफिस पेंट्री में भी छेड़छाड़ हुई। महिला के मुताबिक, एक आरोपी ने कहा कि महिलाओं के साथ रेप इसलिए होता है क्योंकि वे बुर्का नहीं पहनतीं। महिला इंजीनियर का बयान नौ एफआईआर में से एक का हिस्सा है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, धार्मिक भावनाएं आहत करना, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न जैसे आरोप शामिल हैं।

राहुल की दोहरी नागरिकता केस से हाईकोर्ट जज हटे

टीम एक्शन इंडिया

लखनऊः कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता केस से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सुभाष विद्यार्थी ने खुद को अलग कर लिया है। जज ने यह फैसला याचिकाकर्ता की पोस्ट से नाराज होकर लिया है। याचिकाकर्ता ने पोस्ट किया था कि यदि आपने किसी से पैसा लिया है तो उसे वापस कर दें, अन्यथा आपको जेल जाना होगा। हालांकि उसने अपने पोस्ट में जज का जिक्र नहीं किया था। दरअसल 17 अप्रैल एफआईआर को जज ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। अगले ही दिन अपना फैसला बदलते हुए उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को नोटिस जारी किए बिना फैसला करना उचित नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर भारत के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

सरकार का घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने पर जोर

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बार कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद घरेलू एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सामान्य है। बंदरगाहों का संचालन सुचारु है और ग्रामीण रोजगार व आवास योजनाओं को गति दी जा रही है। पश्चिम एशिया में संकट के चलते घरेलू गैस की आपूर्ति के सामने चुनौती पैदा हो गई । इसलिए घरेलू एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने की योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्रीय

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने सोमवार को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में नियमित होने वाली अंतरमंत्रालयी पत्रकार वार्ता में कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति लगभग 70 प्रतिशत तक सुधरकर प्रतिदिन 7000 टन तक पहुंच गई है। ऑटो एलपीजी की बिक्री भी बढ़कर 350 टन प्रतिदिन हो गई है। 3 अप्रैल से अब तक 7000 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं और करीब 1 लाख छोटे सिलेंडर वितरित किए गए हैं।

23 मार्च से अब तक 1.84 करोड़ सिलेंडर की आपूर्ति की गई है।

आपूर्ति सामान्य

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद घरेलू एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सामान्य

हरियाणा के स्कूलों में अब लकड़ियों पर बनेगा मिड-डे मील

टीम एक्शन इंडिया

चंडीगढ़। अमेरिका-इरान की लड़ाई का असर अब हरियाणा के स्कूलों में भी देखने को मिल रहा है। राज्य के कई स्कूलों में मिड-डे मील बनाने को लेकर हो रही परेशानी के मद्देनजर सरकार ने लकडियों पर मिड-डे मील बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं,ताकि स्कूली बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। हरियाणा के कई जिलों ने एलपीजी का संकट चल रहा है। होटल उद्योग इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मिड-डे मील बनाने को लेकर भी समस्या की खबरें आ रही थी। स्कूलों में गैस खत्म है और जिलों की एजेसिंयों द्वारा पहले की तरह नियमित आपूर्ति नहीं की जा रही है। कई जगह तो बच्चों को खाना नहीं मिलने की खबरें भी आई। इस परिस्थिति का संज्ञान लेते हुए निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा ने सोमवार को राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के नाम पत्र जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार यदि स्कूलों में एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति समय पर नहीं हो पाती है, तो मिड-डे मील तैयार करने के लिए वैकल्पिक रूप से लकड़ी का उपयोग किया जा सकता है।

मौलिक शिक्षा हरियाणा के निदेशक की ओर से जारी इस निर्देश में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि वे संबंधित गैस एजेंसियों से समन्वय कर जल्द से जल्द सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करे। इस संबंध में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की मदद भी ले सकते हैं। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि गैस उपलब्ध न होने की स्थिति में विद्यार्थियों के भोजन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। पत्र में उल्लेख किया गया है कि स्कूलों में पढने वाले बच्चों को नियमित रूप से मिड-डे मील उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। ऐसे में आवश्यक होने पर अस्थायी रूप से लकड़ी का उपयोग कर भोजन तैयार किया जा सकता है।

बजट पारित *विश्वविद्यालय नवाचर, शोध कौशल एवं अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों में निभा रहा है अहम भूमिका-मुख्यमंत्री*

तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का 76.07 करोड़ का वार्षिक बजट पारित

पंकज शर्मा

शिमला। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 76.07 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शी वार्षिक बजट पारित कर तकनीकी शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में एक नई दिशा निर्धारित की है। कुलपति एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन की अध्यक्षता में आयोजित वित्त समिति की बैठक में व्यापक विचार-विमर्श के बाद इस बजट को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसे विश्वविद्यालय के शासी मंडल (बीओडी) द्वारा भी अनुमोदित किया गया।

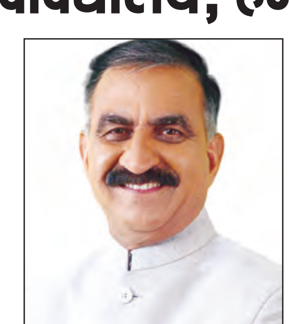

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल पारंपरिक शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को नवाचार, शोध कौशल और विविध सह-शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। यह बजट विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के साथ-साथ उनके सर्वांगीण विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में इन सभी गतिविधियों का नियमित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव होगा।

स्वीकृति

वित्त समिति की बैठक में व्यापक विचार-विमर्श के बाद इस बजट को स्वीकृति प्रदान की गई

उन्होंने कहा कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम, औद्योगिक अनुभव एवं प्रशिक्षण पर विश्वविद्यालय का विशेष फोकस रहेगा, ताकि विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ सकें।

कुलपति डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि विश्वविद्यालय शीघ्र ही पीएच.डी. कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है, जिसे न केवल विश्वविद्यालय परिसर बल्कि इसके संबद्ध संस्थानों में भी लागू किया जाएगा। यह पहल प्रदेश में शोध संस्कृति को सुदृढ़ करने और उच्च शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि यह बजट तकनीकी विश्वविद्यालय की उस प्रगतिशील सोच का परिचायक है, जिसमें शिक्षा, शोध, कौशल विकास और उद्यमिता का संतुलित समावेश है। यह पहल निस्संदेह प्रदेश के तकनीकी शिक्षा परिदृश्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी। शोध एवं नवाचार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पहली बार विशेष बजट का प्रावधान किया गया है।

मणिपुर में प्रदर्शनकारियों-सुरक्षा बलों में झड़प, आंसू गैस छोड़ी

इंफालः मणिपुर में शटडाउन के बीच रविवार रात कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। इंफाल ईस्ट के कोईरेंगेई, इंफाल वेस्ट के उरिपोक और कक्चिंग जिले में मशाल रैलियां निकाली गईं। कक्चिंग में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, स्मोक बम और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। झड़प में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल, 6 अप्रैल को ट्रोंग्लाओबी आवांग लेइकाई एक घर पर बम धमाके में दो बच्चों की मौत हुई थी।

उत्तर भारत

ACTION INDIA

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026

दैनिक एक्शन इंडिया

www.actionindialive.com

कृषि मंत्री श्री नेताम ने मिट्टी एवं बीजों की पूजा की और ट्रैक्टर चलाकर बीजों की बुआई की

कृषि विश्वविद्यालय में मनाया गया अक्ती तिहार, प्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं अनुसंधान प्रक्षेत्रों में भी हुआ अक्ती तिहार का आयोजन

टीम एक्शन इंडिया

रायपुरः कृषि विकास एवं किसान कल्याण कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज अक्ती तिहार के अवसर पर ट्रेक्टर चलाकर सीड ड्रील से धान बीज का रोपण किया और बाड़ी में सब्जियों के बीजों की बुआई की। कृषि मंत्री ने अच्छी फसल के लिए धरती माता से प्रार्थना की और गौ माता को चारा भी खिलाया। उन्होंने इस अवसर पर किसानों को उन्नत बीज, खाद एवं कृषि यंत्र भी वितरित किये। अक्ती तिहार का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त महाविद्यालयों, अनुसंधान प्रक्षेत्रों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में भी किया गया। मंत्री श्री नेताम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अक्षय तृतीया के अवसर पर अक्ती तिहार के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। मंत्री श्री नेताम ने इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र में माटी पूजन, बीज पूजन तथा ठाकुर देवता की पूजा अर्चना कर खेती किसानी के नए कार्यों की शुरूआत की।

समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि हमें कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करते हुए जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों एवं जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है जो मिट्टी और पर्यावरण की सेहत के लिए अधिक सुरक्षित हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को कम करने के लिए सुनियोजित रणनीति बनाई गई है जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी तकनीकी सहयोगी के रूप में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि अक्ती तिहार धरती के प्रति अपनी कृतिज्ञता प्रकट करने का त्यौहार है। हमें सोचना चाहिए कि प्रकृति से हम जितना ले रहे हैं उसके बदले में धरती को क्या वापस कर रहे हैं। अक्ती तिहार के अवसर पर खेती किसानी का कार्य शुरू करने के पहले हम धरती माता से प्रार्थना कर उनसे अनुमति लेते हैं तब हल चलाते हैं। धरती माता को जो क्षति होती है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। श्री नेताम ने कार्यक्रम में ड्रोन का संचालन करने वाली ड्रोन दीदी श्रीमती फुलेश्वरी निषाद को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि एक घरेलू ग्रामीण महिला श्रीमती निषाद ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर ड्रोन दीदी के रूप में लोगों की सेवा कर रहीं हैं, यह प्रशंसनीय है।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ती के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन हम धरती एवं बीजों की पूजा करते हैं ।

ड्रोन का उपयोग तकनीक का प्रदर्शन भी किया जा रहा

आज कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों में भी अक्ती तिहार का आयोजन किया जा रहा है। किसानों के लिए नवीन बीज बुआई तकनीकी एवं कृषि में ड्रोन का उपयोग तकनीक का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र रायपुर द्वारा रासायनिक उर्वरकों का विकल्प विषय पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर विभिन्न जैव उर्वरक एवं जैविक खाद के उपयोग की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि नील हरित काई, अजोला, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, फॉस्फोरस स्थिरीकरण बैक्टीरिया जैसे जैव उर्वरकों तथा हरी खाद के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की कमी पूरी की जा सकती है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को नील हरित काई तथा अजोला खाद के निर्माण का प्रायोगिक प्रदर्शन भी किया गया।

रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर विभिन्न जैव उर्वरक एवं जैविक खाद के उपयोग की जानकारी दी

प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर विभिन्न जैव उर्वरक एवं जैविक खाद के उपयोग की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि नील हरित काई, अजोला, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, फॉस्फोरस स्थिरीकरण बैक्टीरिया जैसे जैव उर्वरकों तथा हरी खाद के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की कमी पूरी की जा सकती है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को नील हरित काई तथा अजोला खाद के निर्माण का प्रायोगिक प्रदर्शन भी किया गया। समारोह में संचालक कृषि श्री राहुल देव, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री महेन्द्र सिंह सवन्नी, छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के एमडी श्री अजय अग्रवाल, कृषि विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. कपिल देव दीपक, संचालक प्रक्षेत्र डॉ. एस.एस. टूटेजा, अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय डॉ. अजय वर्मा, अपर संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री जी.के. पीढ़िया सहित विभिन्न विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक कृषि वैज्ञानिक तथा बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषक व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

गोरखपुर निगम ने कूड़े के पहाड़ को खत्म कर बनाया खूबसूरत पर्यटन स्थल

टीम एक्शन इंडिया

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को गोरखपुर में इको पार्क और इसके सामने से बाघागाड़ा तक जाने वाली फोरलेन सड़क का लोकार्पण करेंगे। इस समग्र परियोजना पर 41.50 करोड़ रुपये की लागत आई है। गोरखपुर नगर निगम ने राप्ती नदी का एकला बंधा कूड़े के पहाड़ को खत्म कर उस स्थान को एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल बताते हैं कि दशकों से इकट्ठा कूड़े के निस्तारण के लिए नगर निगम ने एक कार्ययोजना बनाकर काम शुरू किया और सुखद परिणाम आज सामने है। राप्ती नदी पर राजघाट पुल के समीप एकला बंधा पर कूड़े का विशाल ढेर पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन गया था। इस लिगेसी वेस्ट में मीथेन गैस उत्सजर्न के कारण कई बार स्वतः आग भी लग जाती थी। दुर्गंध और वायु प्रदूषण आसपास की आबादी के स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ था। नगर आयुक्त के अनुसार बायो रेमेडिएशन के माध्यम से नगर निगम ने 2.26 लाख मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट का

> ईको पार्क के सामने फोरलेन सड़क का भी मुख्यमंत्री के हाथों होगा लोकार्पण

निस्तारण कराकर 40 एकड़ भूमि को मुक्त कराया। इतने बड़े क्षेत्रफल में जमीन कूड़ामुक्त हुई तो इसे सिटी फॉरेस्ट और ईको पार्क के रूप में विकसित किया गया। अब लोग यहां प्राकृतिक एवं स्वच्छ वातावरण में पिकनिक मनाने आ सकेंगे। यहां वाकिंग ट्रैक और फुटपाथ बनाए गए हैं, जहां लोग मॉर्निंग और इवनिंग वाक कर सकेंगे। योग और ध्यान के लिए अलग स्थान हैं। बच्चों के लिए भी सुरक्षित किड्स जोन का विकास किया गया है। इसके अलावा नगर निगम ने ईको पार्क के सामने से होकर बाघागाड़ा तक जाने वाले 2.90 किमी लंबे मार्ग पर फोरलेन सड़क बनवा दिया है। इस फोरलेन सड़क के डिवाइडर पर ग्रीन बेल्ट भी विकसित किया गया है।

ईको पार्क एवं फोरलेन सड़क के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छ स्कूल अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। यह अभियान, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सिटी लीडरशिप का विशेष कार्यक्रम है। महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव का कहना है कि स्वच्छ स्कूल अभियान केवल स्वच्छता का कार्यक्रम मात्र नहीं है।

डीबीएस फाउंडेशन ने वर्ष 2025 के लिए 22 इंपैक्ट बिजनेस का चयन किया

टीम एक्शन इंडिया

गुरुग्राम। डीबीएस फाउंडेशन ने वर्ष 2025 के लिए 22 इंपैक्ट बिजनेस का चयन किया है और उन्हें कुल 34.40 करोड़ रुपये (4.9 मिलियन एसजीडी) की ग्रांट देने की घोषणा की है। गुरुग्राम स्थित लर्नर इस सूची में शामिल है, साथ ही भारत से आइक्योर टेकसॉफ्ट और कदम हाट बास्केटरी को भी चुना गया है। यह डीबीएस फाउंडेशन के ग्रांट प्रोग्राम का 11वां संस्करण है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे बिजनेस को समर्थन देना है जो समाज की जटिल समस्याओं के

घोषणा

> कुल 34.40 करोड़ रुपये (4.9 मिलियन एसजीडी) की ग्रांट देने की घोषणा की है

लिए नए और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधान विकसित कर रहे हैं। हर चयनित संस्था को 1.75 करोड़ रुपये (2,50,000 एसजीडी) तक की फंडिंग के साथ-साथ डीबीएस फाउंडेशन और डीबीएस के नेटवर्क से व्यापक सहयोग भी

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन में फरियादियों से संवाद कर सुनीं समस्याएं।

योगी सरकार विश्वनाथ मंदिर और घाट के आसपास लगाएगी डिजिटल लगेज लॉकर

टीम एक्शन इंडिया

वाराणसीः श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों को अब अपने सामान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, कपड़े हों या मंहगे सामान, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए योगी सरकार विश्वनाथ मंदिर और घाट के आसपास डिजिटल लगेज लॉकर लगवाने जा रही है।

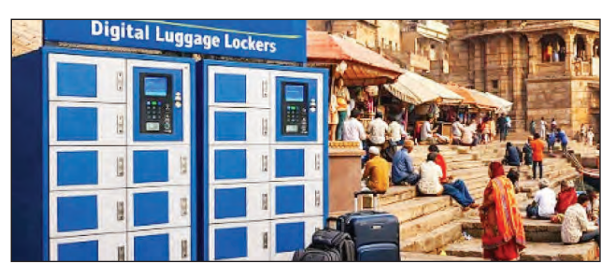

डिजिटल लॉकर में मोबाइल से लेकर सूटकेस तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। डिजिटल लॉकर के इस्तमाल के लिए डिजटल पेमेंट की सुविधा रहेगी। डिजिटल भारत की बानगी देखना हो तो इतिहास से भी प्राचीन शहर काशी में आइये। काशी में अब आपको डिजिटल लगेज लॉकर की सुविधा मिलेगी। जहां अपने कीमती सामानों और कपड़ों को रख कर आप बेफिक्र घाटों पर घूम सकेंगे और गंगा स्नान कर काशीपुराधिपति समेत अन्य मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आस-पास और दशाश्वमेध घाट के पास भी डिजिटल लगेज लॉकर की सुविधा जल्द मिलेगी। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल लगेज लॉकर की व्यवस्था दशाश्वमेध घाट के पास दशाश्वमेध प्लाजा ,गोदौलिया, टाउन हॉल और बेनियाबाग पार्किंग में डिजिटल लॉकर लगाया जाना प्रस्तावित है।

धमतरी में सजेगा युवा उत्सवः प्रतिभा, तकनीक-संस्कृति का महाकुंभ 24-25 अप्रैल को

टीम एक्शन इंडिया

रायपुरः जिले के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और नए अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से 24 एवं 25 अप्रैल को धमतरी में युवा उत्सव 2026- इंटर कॉलेज प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा आयोजन की रूपरेखा तैयार कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इस युवा उत्सव में जिला सहित राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों के युवा पर पंजीयन कर सकते है। अभी तक धमतरी जिला सहित आस-पास के जिलों के 2 हजार से अधिक प्रतिभागी अपना पंजीयन कर चुके है। यह उत्सव केवल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं के आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास और करियर निर्माण का सशक्त मंच बनेगा। आयोजन में 20 से अधिक विधाओं को शामिल किया गया है, जिनमें वाद-विवाद, फोटोग्राफी, एकल एवं समूह नृत्य-गायन, म्यूजिकल बैंड, क्विज, नुक्कड़ नाटक, पारंपरिक वेशभूषा में रैम्प वॉक, आर्ट एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी और फूड फेस्ट प्रमुख हैं।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन शुरू

टीम एक्शन इंडिया

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने सोमवार को बताया कि विभाग की

ओर से संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग का संचालन राजकीय इंटर कॉलेज एवं महाराजा अग्रसेन कॉमर्स कॉलेज, में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत यूपीएससी/यूपीपीएससी,

जेईई, नीट एवं एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्युदय प्रवेश परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 5 जून निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा जून माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम, काउंसिलिंग एवं मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया जून माह के तृतीय सप्ताह में पूर्ण की जाएगी। कोचिंग कक्षाओं का संचालन 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ किया जाएगा।

विकास और संस्कृति का संतुलित मॉडल

विकास के साथ विरासत का सम्मान, योगी सरकार गढ़ रही नए उत्तर प्रदेश की पहचान

टीम एक्शन इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ महापुरुषों की विरासत को सम्मान देने की दिशा में योगी सरकार लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। प्रदेश में एक ओर जहां एक्सप्रेस-वे, मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट सिटी, निवेश और रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रनायकों, संतों, साहित्यकारों और समाज सुधारकों की स्मृतियों को सहेजने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। यही संतुलित सोच योगी सरकार की कार्यशैली को अलग पहचान दे रही है।

प्रेरणास्त्रोत महापुरुषों से जोड़ रही योगी सरकार

सरकार का कहना है कि केवल भौतिक विकास ही पर्याप्त नहीं, बल्कि समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, प्रेरणास्त्रोत महापुरुषों और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के तहत प्रदेश में समय-समय पर महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर बड़े स्तर पर आयोजन किए जा रहे हैं। इनमें बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, महाराजा सुहेलदेव, संत रविदास, कबीरदास, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान व्यक्तित्वों को सम्मानपूर्वक याद किया जाता है।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर 24 से 26 अप्रैल तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीन दिवसीय रश्मिरथी पर्व आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रकवि दिनकर की कालजयी कृति रश्मिरथी के हीरक जयंती वर्ष (75 वर्ष) पर हो रहे इस आयोजन में साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रचिंतन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा।

में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे।

बंदूक से विकास की ओरः सुकमा के तुंगल इको-पर्यटन केंद्र की प्रेरक कहानी

टीम एक्शन इंडिया

रायपुरः सुकमा जिले में वन विभाग की एक सराहनीय पहल ने विकास और पुनर्वास की नई मिसाल पेश की है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में तैयार किया गया तुंगल इको-पर्यटन केंद्र आज आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गया है। सुकमा नगर से मात्र एक किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान पहले उपेक्षित और जर्जर था, लेकिन वन विभाग के प्रयासों से इसे एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। यहाँ बनाए गए आकर्षक टापू और प्राकृतिक वातावरण अब स्थानीय लोगों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहे हैं।

> प्रकृति संरक्षण के साथ-साथ मानव विकास को जोड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है

इस केंद्र की सबसे खास पहल है तुंगल नेचर कैफे, जिसे आत्मसमर्पण पुनर्वास महिला स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाएँ संचालित कर रही हैं। इनमें 5 महिलाएँ वे हैं जिन्होंने नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है, जबकि 5 महिलाएँ नक्सल हिंसा से प्रभावित रही हैं। इन सभी को जगदलपुर और सुकमा के संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए

तैयार किया गया है। आज ये महिलाएँ आत्मविश्वास के साथ पर्यटकों का स्वागत कर रही हैं और सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। जो महिलाएँ कभी संघर्ष और भय के माहौल में थीं, वे अब स्वावलंबन और आत्मसम्मान की मिसाल बन गई हैं। इस पर्यटन केंद्र की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 31 दिसंबर 2025 को शुरू होने के बाद केवल तीन महीनों में, 30 मार्च 2026 तक यहाँ 8 हजार 889 पर्यटक आए। इस दौरान केंद्र ने लगभग 2.92 लाख रूपए की आय भी अर्जित की।

पर्यटक यहाँ स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने के साथ-साथ तुंगल डैम में कयाकिंग, पैडल बोटिंग और बाँस राफ्टिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का भी अनुभव कर रहे हैं।यह पहल साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर जीवन की दिशा बदली जा सकती है। तुंगल इको-पर्यटन केंद्र न केवल पर्यटन का केंद्र है, बल्कि यह उन महिलाओं के साहस, आत्मविश्वास और वन विभाग की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है।

यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि प्रकृति संरक्षण के साथ-साथ मानव विकास को जोड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने आजादपुर मंडी और आसपास के क्षेत्रों का किया निरीक्षण

दिशा-निर्देश

- साफ-सफाई, कूड़ा उठान और बेहतर प्रबंधन को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को आजादपुर मंडी, गुप्ता मार्केट और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर साफ-सफाई, कूड़ा उठान और बेहतर प्रबंधन को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को स्थानीय नागरिकों के आवागमन और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ, निर्धारित समय-सीमा के भीतर और गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना पूरे किए जाएं, ताकि जनता को समय पर सभी आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्लीवासियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं विकसित कर रही हैं

रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों में भी नए विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है और इन्हें समय पर पूरा कर जनता को समर्पित करने के लिए हमारी सरकार निरंतर मिशन मोड में कार्य कर रही है।

सीएम रेखा गुप्ता ने साफ-सफाई, कूड़ा उठान और बेहतर प्रबंधन के दिए निर्देश

सीएम ने सभी संबंधित विभागों को स्थानीय नागरिकों के आवागमन और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ, निर्धारित समयसीमा के भीतर किए जाएं। गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए ताकि जनता को आवश्यक सुविधाएं निर्बाध रूप से मिल सकें। उन्होंने निर्माण कार्यों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर साफ-सफाई, कूड़ा उठान और बेहतर प्रबंधन को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

स्वर्णकांता शर्मा ने नरेश बाल्यान के मामले से खुद को किया अलग

जमानत याचिका

- नरेश बाल्यान ने इसके पहले भी उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पूर्व आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान की मकोका के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इस मामले पर अब कोई दूसरी बेंच 23 अप्रैल को सुनवाई करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून, 2025 को नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। नरेश बाल्यान ने इसके पहले भी उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत याचिका वापस ले ली गई थी। उसके बाद बाल्यान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई, 2025 को बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद बाल्यान ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। दरअसल, वसूली के मामले में 4 दिसंबर, 2024 को नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर, 2024 की रात गिरफ्तार किया था। इससे पहले भाजपा ने नरेश बाल्यान का एक ऑडिया क्लिप जारी किया था, जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और बाल्यान के बीच बातचीत थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का ये मामला 2023 का है। इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है, जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है। कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं। कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है। उसे बल्लू पहलवान और भाजपा नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है।

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की

चुनाव प्रचार

- अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु में डीएमके और मुख्यमंत्री स्टालिन के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगे

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से चेन्नई में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बाद आज चेन्नई में संयुक्त रोड शो का आयोजन किया जाएगा।

इस दौरान अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु में डीएमके और मुख्यमंत्री स्टालिन के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर जारी संदेश में कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ। हम शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और महिला सशक्तिकरण के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। हमने हमेशा एक-दूसरे से सीखा है। केजरीवाल ने तमिलनाडु के लोगों के जीवन को बदलने में स्टालिन के समर्पित शासन द्वारा पैदा किए गए प्रभाव की सराहना की। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है।

बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या, बदले की कार्रवाई में आरोपित घायल

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में सोमवार सुबह पुरानी रंजिश के चलते हिंसक झड़प में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि बदले की कार्रवाई में आरोपित और उसके परिजन भी घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, 20 अप्रैल को सुबह करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि चाकू के वार से घायल एक व्यक्ति को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने इस्माइल को मृत घोषित कर दिया। जांच में सामने आया कि सुबह इस्माइल अपने घर के पास मोहम्मद इरशाद के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान आरोपित दानिश वहां से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि इस्माइल के देखने पर, दोनों के बीच पहले से चली आ रही रंजिश के चलते गाली-गलौज शुरू हो गई, जो जल्द ही झगड़े में बदल गई। इसी दौरान शाहिद अली नामक व्यक्ति मौके पर पहुंचा और झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आरोपित ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी आंख में चोट आई।

इसके बाद दानिश चाकू लेकर आया और इस्माइल के सीने, पेट और सिर पर कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के बेटे जफर उर्फ जीशान और फैजान मौके पर पहुंचे और बदले की नीयत से आरोपित दानिश व उसके परिजनों पर हमला कर दिया। इस झड़प में दानिश के सीने सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं। घायल दानिश को भी जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर दिल्ली के अस्पताल में लड़ रहे जिंदगी की जंग

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली। अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जदरान इस समय एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं। वह दिल्ली के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार 39 वर्ष के होने जा रहे जदरान को हेमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस नामक जानलेवा बीमारी हुई है।यह बीमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देती है, जिससे शरीर में अत्यधिक सूजन और संक्रमण फैल जाता है। इसका असर बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन और अन्य अंगों पर पड़ता है। आमतौर पर यह बीमारी बच्चों में देखी जाती है, लेकिन वयस्कों में भी हो सकती है। शापूर जदरान ने 2009 से 2020 के बीच अफगानिस्तान के लिए 44 वनडे और 36 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भारत प्रतिभा सम्मान परिषद द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 में भाग लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुभाष चंद्र बोस को 'राष्ट्रीय पुत्र' घोषित करने की मांग

टीम एक्श इंडिया
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय पुत्र घोषित करने और आजाद हिन्द फौज को आजादी का श्रेय देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि वो न्यायिक समय को बर्बाद कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता पिनाकपानी मोहंती को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको उच्चतम न्यायालय में प्रवेश करने पर रोक लगाई जा सकती है।

जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर जवाब के लिए ईडी ने मांगा समय

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट से समय मांगा है। एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 17 अप्रैल को जैकलीन की इस अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया था। इस मामले में जैकलीन फर्नांडीज आरोपित हैं। जैकलीन ने ईडी के केस को निरस्त करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जैकलीन की

याचिका खारिज कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के आदेश पर मुहर लगाते हुए जैकलीन की याचिका खारिज की थी। इस मामले में जैकलीन फर्नांडीज जमानत पर हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को जैकलीन को जमानत दी थी। 31 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने जैकलीन के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 अगस्त, 2022 को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपित बनाया था। ईडी अप्रैल, 2025 में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपये से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे। सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था। इन गिफ्टों में 52 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है। जैकलीन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दायर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। ये याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। जैकलीन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। जैकलीन ने कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने तो उसके साथ फर्जीवाड़ा किया ही, अदिति सिंह ने भी फर्जीवाड़ा किया।

Yogi Adityanath
Chief Minister, Uttar Pradesh

Nand Gopal Gupta 'Nandi'
Minister of Industrial Development
Uttar Pradesh

Jaswant Saini
Minister of State for Industrial Development
Uttar Pradesh

UP is India's Growth Engine...
In Greater Noida, realise your industrial vision

Greater Noida Industrial Development Authority Invites applications for allotment of
INDUSTRIAL PLOTS
SCHEME CODE- ONLINE-IND-02-OC-01/2026

In Sector-ECOTECH-1, EXTN.01, ECOTECH-06, ECOTECH-08, ECOTECH-10, ECOTECH-11, Sector-16

HOW TO APPLY

The brochure and application form for the scheme shall be available online only on http://niveshmitra.up.nic.in. Payment of Rs. 60,180/- is also payable against form cost of Rs. 1,000/- and Rs. 50,000/- as processing fee alongwith 18% GST apart from registration money.

The brochure and application form for the scheme shall be available online only on http://niveshmitra.up.nic.in / www.greaternoidaauthority.in

Selection on Objective Criteria Basis
- 90 Marks on these criteria & 10 for Interview
- Sun Rise or Focus Sector
- FDI/FCI, Fortune 500 & Global 500
- Export Unit
- Employment Generation
- Ancillary unit of an existing industry or Expansion
- Start up
- Financial parameters like - Net worth Turnover, Liquidity vis a vis project cost
- Women, SC/ST, Entrepreneur with any person of disability

*60% marks to Qualify for interview

S. No.	Plot Number	Sector	Area of Plot (sq. mtr)	*Registration Amount (Rs.)
1	1	ECOTECH-11	20246.00	52388550/-
2	12	ECOTECH-11	12000.00	31857600/-
3	13	ECOTECH-11	16285.00	42645530/-
4	3	ECOTECH-11	24770.00	59579281/-
5	11A	ECOTECH-11	12000.00	31857600/-
6	2	ECOTECH-11	13400.00	35382700/-
7	73	ECOTECH-01, EXTN.01	20229.20	52486682/-
8	62	ECOTECH-01, EXTN.01	20328.60	52699863/-
9	61	ECOTECH-01, EXTN.01	20354.00	52753497/-
10	60	ECOTECH-01, EXTN.01	20354.00	52753497/-
11	74	ECOTECH-01, EXTN.01	20229.20	52486682/-
12	1	ECOTECH-01, EXTN.01	32880.00	79533432/-
13	82C	ECOTECH-01, EXTN.01	9656.00	25957259/-
14	09A	ECOTECH-10	22884.00	56582978/-
15	09B	ECOTECH-10	10443.00	27938158/-
16	1D	SECTOR-16	18560.00	48372928/-
17	1B	SECTOR-16	29046.00	64394982/-
18	16A	ECOTECH-08	13407.00	35399843/-
19	12A	ECOTECH-08	10776.00	28776230/-
20	16B	ECOTECH-08	13407.00	35399843/-
21	7A	ECOTECH-08	9065.00	24469155/-
22	7B	ECOTECH-08	12613.00	33400485/-
23	A2	ECOTECH-06	100000.00	220850000/-
24	5A	SECTOR-16	11111.00	29619704/-

*Registration amount is 10% of the premium of the plot based on rate of allotment of industrial plot for year 2025-2026 which is under revision and if so revised before allotment, then new rate shall be applicable on applicants.

For registration enquiry contact mobile no. 9634301156, For Scheme related query contact mobile no. 9205691009

Scheme Opening & Registration Start Date 11.04.2026 | Scheme & Registration Closes on 12.05.2026

Greater Noida Industrial Development Authority
Plot No. 01, Knowledge Park-04, Greater Noida - 201308, Distt.-Gautam Budh Nagar (U.P.)
Helpline Center No. : 0120-2336046, 2336047, 2336048, 2336049
Ph.: 0120-2336030-33 I Email: authority@gnida.in I Website: www.greaternoidaauthority.in
ECOTECH GREATER NOIDA GREENER PASTURES
Follow us on /OfficialGNIDA

समाधान शिविर सुशासन के संकल्प को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रभावी माध्यम : उपायुक्त

आमजन की समस्याओं का अधिकारी जल्द करें समाधान, बार-बार कार्यालय के न लगाने पड़ें चक्कर

समाधान शिविर

उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में समाधान शिविर का आयोजन हुआ

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला मुख्यालय पर समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने समाधान शिविर में बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए सिंचाई विभाग के करनाल व इंद्री के कार्यकारी अभियंताओं और फूड सेफ्टी ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडल स्तरों पर आज समाधान शिविर आयोजित हुए, जिनमें करनाल मुख्यालय पर 13, नीलोखेड़ी उपमंडल में एक, इंद्री उपमंडल में एक व असंध उपमंडल में दो शिकायतें प्राप्त हुईं। घरौंडा उपमंडल में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निदेशानुसार हर सोमवार और वीरवार को जिला व उपमंडल स्तर पर सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। समाधान शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लें और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें, ताकि लोगों का सरकार और प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर सरकार के सुशासन के संकल्प को जमीनी स्तर पर लागू करने का एक प्रभावी माध्यम है। सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान हो और उसकी गुणवत्तापूर्ण एटीआर पोर्टल पर अपलोड की जाए, ताकि शिकायत दोबारा लंबित न रहे। ज्यादा पुरानी शिकायतों पर फोकस करके, उनका जल्द निपटान सुनिश्चित करें।

शुक्रवार को समाधान प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक से पहले पहले सभी शिकायतों का उचित निराकरण या आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि सभी नागरिक सरकार द्वारा आयोजित इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने सुनी हलका वासियों की समस्याएं

जनसुनवाई

इस अवसर पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सोमवार को अपने फार्म हाउस पर जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत हलका वासियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान स्थानीय निवासियों ने अपने गांवों से जुड़ी विकास संबंधी मांगें रखीं। इनमें मुख्य रूप से कोहंड में विद्यालय की बिल्डिंग बनवाने, गांव तारपुर के पास खादर एरिया में डेरे के रास्ते को पक्का करवाने, गांव कालरम में चौपाल तथा हॉल का निर्माण करवाने, पंजू राम कॉलोनी में पीने के पानी की नई पाइप लाइन बिछवाने, गांव गुढा में महिला मीटिंग हॉल का निर्माण करवाने और गांव रसिन में बैंक्वेट हॉल बनवाने आदि की मांगें शामिल थीं।

उन्होंने ग्रामीणों द्वारा उठाई गई सभी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से लिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान उनकी प्राथमिकता है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि प्रदेश सरकार समूचे प्रदेश में समान रूप से विकास परियोजनाओं को तेज गति से बढ़ा रही है, ताकि जिस परियोजना को जिस मकसद के लिए बनाया जा रहा है, वो पूरा हो और नागरिकों को उनका लाभ मिले।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग विकास कार्यों से सम्बन्धित अपनी मांग हम तक पहुंचाने का कार्य करें, उसके बाद योजनात्मक तरीके से उस कार्य को धरातल पर लाना उन पर छोड़ दें तथा आपसी मन मुटाव छोडकर हो रहे विकास कार्यों में अपनी सहभागिता रखें ताकि कार्य में तेजी आए और निगरानी रहे। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

नई खरीद नीति के खिलाफ भड़के किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर की तालाबंदी

टीम एक्शन इंडिया
रादौर, 20 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) और अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों ने रादौर मार्केट कमेटी कार्यालय पर तीन घंटे तक तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीकेयू के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि फसल खरीद के नए नियम किसानों के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा मंडियों को कमजोर कर बंद करने की है, जिसके चलते किसानों को पोर्टल और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाओं में उलझाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक प्रणाली में समय अधिक लगने से खरीद प्रक्रिया धीमी हो गई है, जबकि नमी का बहाना बनाकर फसल खरीद टाली जा रही है।

वहीं किसान सभा के जिला प्रधान जरनैल सिंह सांगवान ने कहा कि उठान कार्य धीमा होने के कारण किसानों को भुगतान समय पर नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से नई व्यवस्था में बदलाव कर पुरानी प्रणाली से खरीद शुरू करने की मांग की। साथ ही बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए गेहूं पर 500 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने की मांग उठाई। सांगवान ने आरोप लगाया कि सरकार कृषि क्षेत्र को निजी कंपनियों के हवाले करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने सब्सिडी, बीज, उर्वरक, सिंचाई और विपणन से जुड़ी योजनाओं को बचाने की मांग की। साथ ही टैरिफ बढ़ोतरी, स्मार्ट मीटर और सीड बिल को रद्द करने, ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग भी रखी। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

जठलाना में सट्टा खाईवाली करते व्यक्ति काबू

टीम एक्शन इंडिया
रादौर, 20 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : जठलाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को सट्टा खाईवाली करते हुए रंगे हाथों काबू किया है।

आरोपी के पास से नगदी भी बरामद की गई है। पुलिस को दी शिकायत में मुख्य सिपाही राहुल पंजेटा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सतपाल उर्फ पाला राम लोगों से सट्टा लगवाने का कार्य करता है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी को सट्टा लगवाते हुए पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 4,130/- रुपये की नगदी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीओ और बेल जंपरों पर पुलिस का शिकंजा, 4 माह में 93 गिरफ्तार

टीम एक्शन इंडिया
रादौर, 20 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : जिला पुलिस ने वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इस वर्ष अब तक 93 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें 21 उद्घोषित अपराधी (पीओ) और 72 बेल जंपर शामिल हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में विभिन्न टीमों द्वारा 1 जनवरी से 20 अप्रैल तक यह अभियान चलाया गया। इस दौरान अलग-अलग मामलों में वांछित आरोपियों की धरपकड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस टीमों की सराहना करते हुए कहा कि यह सफलता कर्मियों की कड़ी मेहनत और सतर्कता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार ऐसे अभियान चलाती रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मोस्ट वांटेड, पीओ, बेल जंपर और पैरोल जंपर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

न्यूज फ्लैश

सोनीपत सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर के दौरान प्राप्त हुई 17 शिकायतें

सोनीपत, 20 अप्रैल।
उपायुक्त नेहा सिंह ने लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें। जिससे शिकायतकर्ता को किसी भी तरह की परेशानी न हो और बार-बार सचिवालय के चक्कर न काटने पड़े।

सोमवार को आयोजित समाधान शिविर के दौरान 17 शिकायतें प्राप्त हुई। समाधान शिविर का आयोजन उपायुक्त नेहा सिंह की अध्यक्षता में किया गया। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। समाधान शिविर के दौरान विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई।

गांव जागसी निवासी रामकुमार ने उपायुक्त को शिकायत दी कि उसकी पेंशन काट दी गई है उसकी पेंशन दोबारा से चालू करवाई जाएं, गांव हुल्लाहेड़ी निवासी करतार सिंह ने उपायुक्त को शिकायत दी कि गांव में जाने वाले रास्ते को रोक दिया गया है। ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बनाया जा रहा है इस प्रकार हो रहे अवैध कब्जे को रोका जाए, मुंडलाना के ग्रामीणों ने उपायुक्त को शिकायत दी कि गांव में जिस जमीन पर उनके प्लाट काटे गए थे वहां पर सरपंच द्वारा शमशान घाट का निर्माण करवाया जा रहा है कृपा उसे रोका जाए, सरसाड के ग्रामीणों ने उपायुक्त को स्वामित्व योजना के द्वारा मालिकाना हक दिलवाने के लिए शिकायत दी,इसके अलावा परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय ठीक करवाने बारे, वृद्धावस्था पेंशन बनवाने बारे, भू राजस्व से संबंधित, अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ एफआईआर करवाने बारे की शिकायतें प्राप्त हुई। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।

इस दौरान सीटीएम सिमरन, नगर निगम जॉइंट कमिश्नर मीतू धनखड़, एसीपी अमित कुमार, डीआरओ सुशील शर्मा, डीडीपीओ मनीष मलिक, तहसीलदार कीर्ति व अन्य विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

गन्नौर लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर के दौरान प्राप्त हुई 6 शिकायतें

गन्नौर। गन्नौर लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर के दौरान 6 शिकायतें प्राप्त हुई। समाधान शिविर का आयोजन एसडीएम प्रवेश कादियान की अध्यक्षता में किया गया। एसडीएम प्रवेश कादियान ने सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।

समाधान शिविर के दौरान अभिषेक शर्मा पटेल नगर निवासी ने एसडीएम को शिकायत दी कि उसके प्लांट के सामने बिजली का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। ट्रांसफॉर्मर को गली के कॉर्नर पर शिफ्ट करवाने का कष्ट करें जिससे वह मकान बना सके, एक अन्य शिकायत रणधीर सनपेड़ा निवासी ने एसडीएम को दी कि उसके खेतों से बिजली के तार काफी नीचे से गुजर रहे हैं, जिससे दुर्घटना होने का खतरा है कृपा बिजली की लाइन को ठीक करवाया जाए। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र में गलत बिजली का मीटर दर्ज होने की शिकायत, बिजली व पानी की शिकायतें प्राप्त हुई। परिवार पहचान पत्र में आए सत्यापित करवाने बारे शिकायती प्राप्त हुई। एसडीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो निश्चित समय अवधि में सभी शिकायतों का समाधान किया जाए, जिससें शिकायतकर्ता को बार-बार सचिवालय के चक्कर न लगाने पड़े। समाधान शिविर के बाद एसडीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों से पिछली पेंडिंग शिकायतो पर चर्चा की ओर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए की पिछली कोई भी समाधान शिविर की शिकायत पेंडिंग न हो सभी को पोर्टल पर अपडेट किया जाए।

मोबाइल मेडिकल यूनिट ने की 95 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच

टीम एक्शन इंडिया
रादौर, 20 अप्रैल (कुलदीप सैनी) :
सांसद नवीन जिंदल की पहल पर संचालित नवीन जिंदल फाउंडेशन की मोबाइल मेडिकल यूनिट ने सोमवार को उपमंडल के गांव हिरण छप्पर और हडतान माजरी में पहुंचकर ग्रामीणों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं। इस दौरान चिकित्सकों की टीम ने दोनों गांवों में कुल 95 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की, जिनमें रक्तचाप, शुगर सहित सामान्य बीमारियों की जांच शामिल रही। 13 मरीजों के रक्त परीक्षण भी किए गए और जरूरतमंदों को मौके पर ही निःशुल्क दवाइयां व चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। सांसद कार्यालय प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में परेशान न हो। ह्यस्वस्थ रादौर अभियानञ्च के तहत संचालित यह मोबाइल यूनिट लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें संतुलित आहार, स्वच्छता और नियमित व्यायाम के प्रति भी प्रेरित कर रही है।

अर्बन चैलेंज फंड से विकास को मिलेगी नई रफ्तार: मेयर

दृष्टिकोण

करनाल ने पहले भी स्वच्छता और सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से आयाम स्थापित किए हैं

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। महापौर रेणु बाला गुप्ता ने केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) का स्वागत करते हुए इसे शहरों के समग्र, सुदृढ़ और दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरगामी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि करनाल ने पहले भी स्वच्छता और सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से अनेक आयाम स्थापित किए हैं। अब इसी क्रम में यूसीएफ के माध्यम से विकास की गति और तेज की जाएगी। मेयर ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन व प्रेरणा से शुरू किया गया यह फंड भारत के शहरी विकास के स्वरूप को नई दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल द्वारा यूसीएफ के संचालन संबंधी महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद करनाल सहित देश के शहरों के सर्वांगीण विकास को नई गति मिलने की ठोस संभावनाएं बनी हैं।

मेयर ने बताया कि एक लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से संचालित यह फंड अगले पांच वर्षों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये के शहरी निवेश को गति देगा, जिसमें द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत तक केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि कम से कम 50 प्रतिशत राशि बाजार आधारित स्रोतों– जैसे बैंक ऋण, नगरपालिका बॉण्ड तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी से जुटाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि यूसीएफ के माध्यम से पुराने शहरी क्षेत्रों और पारंपरिक बाजारों के पुनर्विकास, शहरी परिवहन और अंतिम छोर तक संपर्क व्यवस्था, गैर-मोटर चालित परिवहन, जल आपूर्ति, सीवरेज और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिवर्तनकारी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, छोटे शहरों के लिए ऋण पुनर्भुगतान गारंटी उप-योजना उन्हें पहली बार बाजार आधारित वित्तपोषण तक पहुंच प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।

मेयर ने विश्वास व्यक्त किया कि करनाल, जो पहले ही स्वच्छता और समग्र विकास के क्षेत्र में प्रदेश और देश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुका है, इस योजना के माध्यम से और अधिक सशक्त होकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि करनाल स्मार्ट सिटी के रूप में निरंतर प्रगति कर रहा है और यूसीएफ के सहयोग से शहर के बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं और शहरी सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाया जा सकेगा। यह फंड केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहरों को सुशासन, बेहतर योजना और वित्तीय सुदृढ़ता की दिशा में भी प्रेरित करता है। इससे करनाल को एक स्वच्छ, आधुनिक, सुरक्षित और निवेश के लिए आकर्षक शहर के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध, देश की आधी आबादी का अपमान: रेनू बाला

पत्रकार वार्ता

कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने संसद में इस विषय पर व्यवधान उत्पन्न किया

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस
करनाल।
भाजपा जिला कार्यालय कर्ण कमल में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर की मौजूदगी मे नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषय को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको नगर निगम महापौर मेयर रेनू बाला गुप्ता द्वारा सम्बोधित किया गया।

भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर की अध्यक्षता में हुई इस पत्रकार वार्ता में पार्षद सुदेश रानी, बेबी पाल, मंजू खैंची, सोनिया काम्बोज, प्रियंका काठपाल, पायल अरोड़ा एवं जिला महामंत्री सुभाष कश्यप, मानव पुरी, जिला मीडिया प्रभारी डा. अशोक कुमार के अतिरिक्त जिला कार्यालय प्रमुख मदन गुर्जर विशेष तौर पर मौजूद रहे।

मेयर रेनू बाला गुप्ता ने कहा कि विपक्षी दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करके देश की आधी आबादी का अपमान करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इससे आज देश के सामने महिला हितों के विरोधियों का चेहरा स्पष्ट हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने संसद में इस महत्वपूर्ण विषय पर जिस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं के अधिकारों से जुड़े इस ऐतिहासिक अवसर पर भी राजनीति करना नारी शक्ति के सम्मान के अनुरूप नहीं है।

मेयर ने विश्वास जताया कि देश की महिलाएं जागरूक हैं और वे यह भलीभांति समझती हैं कि कौन उनके सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रहा है और कौन इसमें बाधा बन रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश की महिलाएं अपने अधिकारों और सम्मान के पक्ष में सशक्त निर्णय लेंगी और ऐसे कृत्यों का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब अवश्य देंगी।

माताओं बहनों को उनके हक से वंचित करने का खामियाजा विपक्षी दलों को पड़ेगा भुगतना : प्रवीण लाठर

जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर ने कहा कि विपक्षी दलों ने जिस प्रकार माताओं और बहनों को उनका न्यायोचित हक देने से वंचित किया गया है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और अब देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली इस देश की महिलाएं अब कांग्रेस और उसके महिला विरोधी गठबंधन के खिलाफ दृढ़ता और एकजुटता के साथ खड़ी होंगी।

भेड़ चोरी मामले में आरोपी रिमांड पर, चोरी की भेड़ें बरामद

टीम एक्शन इंडिया
रादौर, 20 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : खेड़ी लक्खासिंह चौकी पुलिस ने भेड़ चोरी के मामले में एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर रिमांड पर लिया और उससे चोरी की भेड़ें बरामद कर ली हैं। आरोपी को बाद में अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चौकी इंचार्ज परमवीर सिंह ने बताया कि 13 मार्च को गांव हूड़ियां निवासी जरनैल सिंह ने शिकायत दी थी कि 5/6 मार्च की रात अज्ञात चोर उसकी 15 भेड़ें कार में लादकर चोरी कर ले गए। इस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

तफ्तीश के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी हाकम सिंह उर्फ काकू निवासी गांव बुडैन (जिला जींद) एक अन्य मामले में जिला जेल अंबाला में बंद है और उसने इस वारदात को कबूल किया है। पुलिस ने उसे अदालत से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने 7 मार्च को गांव गुंदियाना में भी भेड़ चोरी की वारदात कबूल की। रिमांड के दौरान आरोपी की निशानदेही पर चोरी की भेड़ें बरामद की गईं है।

संपादकीय

कचरा प्रबंधन और भारत के प्रयास

विश्व की पर्यावरणीय व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कचरे के कारण बड़ी समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। न केवल मनुष्य समाज बल्कि समस्त जीव-जगत और वनस्पतियां भी कचरा जनित प्रदूषण का दंश झेलने को अभीशप्त हैं। हवा, पानी और जमीन सब इस प्रदूषण की चपेट में है। इससे वनस्पति और सारा जीव-जगत बीमारियों और जीवन संकट से गुजर रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में विश्व की 18 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और वैश्विक नागरिक अपशिष्ट में भारत की हिस्सेदारी 12 फीसद है। भारत प्रतिवर्ष 620 लाख टन कचरा पैदा करता है। इसमें से केवल 430 लाख टन ही एकत्रित होता है और 120 लाख टन ही उपचारित होता है। 310 लाख टन लैंड फिल में डाल दिया जाता है। शेष यहां-वहां पड़ा रहता है और जंगलों, ढलानों, खेतों, जल संसाधनों को प्रदूषित करता रहता है। उसमें से कुछ खुले में जलाया जाता है। यहविषैली गैसों को स्थानीय स्तर पर फैला कर गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। हालांकि सरकार इसके लिए समय-समय पर नियम बनाती है। इनके खराब क्रियान्वयन के चलते स्थिति में कोई सुधार आता दिखाई नहीं देता है। गरीब बस्तियों के नजदीक डंपिंग, प्रबंधन और लापरवाही से संबंधी डेटा के अभाव के चलते नीति निर्माण और क्रियान्वयन में बाधा होती है। उच्चतम न्यायालय ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 सख्ती से लागू किए जाएं और लापरवाही करने वालों को दंडित करने के भी प्रावधान किए गए। मुख्य निर्देश निम्न हैं- ठोस कचरा चार भागों में अलग करके एकत्र किया जाए। 1. गीला कचरा, जिसमें रसोई अपशिष्ट, भोजन,फल,सब्जियां आदि शामिल हैं। 2. सूखा कचरा, जिसमें प्लास्टिक,कागज, धातु, कांच शामिल हैं। 3. सैनिटरी, नैपकिन, डायपर आदि के अलग अलग निपटारे की व्यवस्था करनी होगी। 4. विशेष, श्रेणी में बल्ब, बैटरी, दवाइयां आदि के लिए विशेष अधिकृत इकाइयों को ही संशोधित करने के लिए देना होगा। गीले कचरे से मीथेन बना कर ईंधन के लिए प्रयोग करना। खास कर 100 किलो दैनिक सूखा अपशिष्ट, 40,000 लीटर दैनिक पानी उपयोग करने वाली और 20,000 वर्ग मीटर में फैली इकाइयां थोक अपशिष्ट उत्पादक घोषित की गई हैं, जिन्हें गीला कचरा अपने परिसर में ही प्रसंस्कृत करना पड़ेगा। सूखा कचरा रिकवरी फैसिलिटी को पुनः चक्रीकरण के लिए देना होगा। सूखे कचरे में से जिसका पुनः चक्रीकरण संभव नहीं होगा उसके पेलेट्स बना कर सीमेंट प्लांट और उर्जा उत्पादक इकाइयों को ईंधन के रूप में देना होगा, जिसकी मात्रा 5 फीसद से बढ़ा कर 15 फीसद की गई है। किसी भी तरह के पुनः चक्रीकरण या उपयोग के योग्य कचरे को ही लैंड फिल में डालने की अनुमति होगी। आम कचरा वहां डालने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पुराने संचित अपशिष्ट को धीरे-धीरे खत्म करने के लिए योजना बनानी होगी।

नई दिल्ली कार्यालय
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

चंडीगढ़ कार्यालय
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

सोनीपत कार्यालय
ऑफिस no. 11, ग्राउंड फ्लोर पवन मेगा मॉल सुभाष चौक सोनीपत

शिमला कार्यालय
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

ऊना कार्यालय
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में 4 आत्महत्याएँ

डॉ. सत्यवान सौरभ

> “इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर दिखने वाली चमक-दमक एक ऐसी दुनिया का निर्माण करती है, जो वास्तविकता से बहुत दूर होती है। लेकिन छात्र इसे वास्तविक मानकर अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जब उन्हें लगता है कि वे इस आदर्श जीवन से पीछे हैं, तो उनमें असंतोष और निराशा बढ़ने लगती है। फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुरखाइम ने आत्महत्या को केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या के रूप में देखा था। उनका अनोमिक सुसाइड सिद्धांत बताता है कि जब समाज के नियम और अपेक्षाएँ व्यक्ति के लिए अस्पष्ट या असंतुलित हो जाती हैं”

भारतीय तकनीकी शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थान, जिन्हें कभी सपनों की फैक्ट्री कहा जाता था, आज कई युवाओं के लिए मानसिक दबाव के कारखाने बनते जा रहे हैं। हरियाणा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में महज दो महीनों के भीतर चार छात्रों की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह केवल चार जिंदगियों का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे तंत्र की विफलता है जो प्रतिभा को तराशने के बजाय उसे तोड़ रहा है। फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच हुई ये घटनाएँ अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि एक खतरनाक सिलसिले का संकेत देती हैं—जहाँ एक घटना के बाद दूसरी घटना घटती चली जाती है, जैसे निराशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल रही हो। दीक्षा दूबे का सुसाइड नोट—मैं कुछ करके नहीं दिखा पाई—सिर्फ एक छात्रा की पीड़ा नहीं, बल्कि उस मानसिकता का आईना है, जिसमें ह्यकुछ करके दिखानाह्न ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बना दिया गया है। भारत में जे ई ई मैंस और जे ई ई अडवांस जैसी परीक्षाएँ लंबे समय से सफलता की कुंजी मानी जाती रही हैं। लाखों छात्र वर्षों तक दिन-रात मेहनत करते हैं ताकि वे इन परीक्षाओं में सफल होकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र जैसे संस्थानों में प्रवेश पा सकें। लेकिन विडंबना यह है कि जिस संस्थान में प्रवेश को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है, वही कई छात्रों के लिए मानसिक संघर्ष का मैदान बन जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद छात्रों को न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होता है, बल्कि उन्हें हर मोर्चे पर खुद को साबित करने का दबाव झेलना पड़ता है। 75 प्रतिशत उपस्थिति का नियम, लगातार असाइनमेंट और प्रोजेक्ट, सेमेस्टर परीक्षाओं का तनाव और प्लेसमेंट की अनिश्चितता—ये सब मिलकर छात्रों के मन पर एक अदृश्य लेकिन भारी बोझ डालते ह यह दबाव केवल शैक्षणिक नहीं होता, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भी होता है। जब एक छात्र, जो अपने स्कूल या कोचिंग में सबसे आगे रहा हो, अचानक खुद को सैकड़ों प्रतिभाशाली छात्रों के बीच पाता है, तो उसकी आत्म-छवि प्रभावित होती है। पहले जहाँ वह खुद को सबसे बेहतर मानता था, वहीं अब वह खुद को सामान्य या कई बार कमजोर महसूस करने लगता है। यह बदलाव कई छात्रों के लिए मानसिक रूप से बहुत कठिन होता है। वे अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाते और धीरे-धीरे आत्म-संदेह और हीनभावना का शिकार हो जाते हैं। इस पूरे संकट में परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में शिक्षा को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। माता-पिता अपने बच्चों से बड़ी उम्मीदें रखते हैं, और यह उम्मीद कई बार अनजाने में दबाव में बदल जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि युवाओं में आत्महत्या के मामलों में पारिवारिक दबाव एक प्रमुख कारण होता है। विशेष रूप से उन छात्रों के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, यह दबाव और भी अधिक होता है। उनके माता-पिता अपनी सीमित आय का बड़ा हिस्सा उनकी पढ़ाई पर खर्च करते हैं, और बदले में उनसे सफलता की अपेक्षा करते हैं। ऐसे में यदि छात्र किसी भी कारण से अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाता, तो उसे लगता है कि उसने न केवल खुद को, बल्कि अपने पूरे परिवार को निराश कर दिया है। सोशल मीडिया ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है। आज का युवा लगातार दूसरों की सफलता और खुशहाल जीवन की झलकियों से घिरा रहता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर दिखने वाली चमक-दमक एक ऐसी दुनिया का निर्माण करती है, जो वास्तविकता से बहुत दूर होती है। लेकिन छात्र इसे वास्तविक मानकर अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जब उन्हें लगता है कि वे इस आदर्श जीवन से पीछे हैं, तो उनमें असंतोष और निराशा बढ़ने लगती है। फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुरखाइम ने आत्महत्या को केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या के रूप में देखा था। उनका अनोमिक सुसाइड सिद्धांत बताता है कि जब समाज के नियम और अपेक्षाएँ व्यक्ति के लिए अस्पष्ट या असंतुलित हो जाती हैं, तो वह खुद को अलग-थलग महसूस करने लगता है। यही स्थिति आज कई तकनीकी संस्थानों में देखने को मिलती है। छात्र एक ऐसे वातावरण में होते हैं जहाँ उनसे बहुत अधिक अपेक्षाएँ की जाती हैं, लेकिन उन्हें उतना भावनात्मक या सामाजिक समर्थन नहीं मिलता। परिणामस्वरूप, वे भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए यह समस्या और भी गहरी होती है। वे अचानक एक ऐसे वातावरण में पहुँच जाते हैं, जहाँ भाषा, जीवनशैली और सामाजिक व्यवहार सब कुछ अलग होता है। उन्हें अपने आसपास के लोगों से जुड़ने में कठिनाई होती है। यह अलगाव धीरे-धीरे अकेलेपन में बदल जाता है, और अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। कई छात्र अपनी समस्याओं को किसी से साझा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करना कमजोरी की निशानी है। महिला छात्रों के लिए यह संघर्ष कई स्तरों पर होता है। उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ सुरक्षा, सामाजिक अपेक्षाओं और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। कई बार उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि उन्हें खुद को साबित करना है, न केवल एक छात्र के रूप में, बल्कि एक महिला के रूप में भी। यह दोहरा दबाव उनके मानसिक स्वास्थ्य को और अधिक प्रभावित करता है। संस्थागत स्तर पर भी कई कमियाँ सामने आती हैं। अधिकांश तकनीकी संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ पर्याप्त नहीं हैं। एक या दो काउंसलर सैकड़ों छात्रों की समस्याओं को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं होते। कई बार छात्र काउंसलिंग लेने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे उनकी छवि पर असर पड़ेगा। इसके अलावा, मेंटरशिप सिस्टम भी कई बार प्रभावी नहीं होता। कुछ मामलों में यह छात्रों के लिए सहायक होने के बजाय अतिरिक्त दबाव का कारण बन जाता है। चार आत्महत्याओं के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम—जैसे जांच समिति का गठन, काउंसलिंग सेवाओं में सुधार और छुट्टियों की घोषणा—महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। यह समस्या केवल तात्कालिक उपायों से हल नहीं होगी। इसके लिए दीर्घकालिक और व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था को यह समझना होगा कि छात्र केवल अंक और रैंक नहीं हैं, बल्कि वे भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं वाले इंसान हैं। समाधान के लिए सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। हर संस्थान में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित काउंसलर होने चाहिए, और छात्रों को बिना किसी डर या शर्म के उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, शैक्षणिक नियमों में लचीलापन लाना भी आवश्यक है।

सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा की प्रतिबद्धता

सुरेश सिंह बैस शाश्वत

किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सफलता केवल उसके संविधान या नीतियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन व्यक्तियों पर भी निर्भर करती है जो इन नीतियों को धरातल पर लागू करते हैं। 21 अप्रैल को मनाया जाने वाला लोक सेवा दिवस (सिविल सर्विसेज डे) हमें उन कर्मयोगी अधिकारियों और कर्मचारियों के योगदान को पहचानने का अवसर देता है, जो निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र निर्माण में लगे रहते हैं। भारत में सिविल सेवा की परंपरा केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के विकास, सामाजिक न्याय और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का एक सशक्त माध्यम है। जब हम प्रशासन की बात करते हैं, तो यह केवल फाइलों और कार्यालयों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सीधे आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है—चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून-व्यवस्था हो या विकास योजनाएँ। लोक सेवा का मूल भाव सेवा है—न कि सत्ता। एक सच्चा लोकसेवक वही है, जो अपने अधिकारों का उपयोग जनता के कल्याण के लिए करता है और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ निभाता है। आज के समय में, जब भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और प्रशासनिक जटिलताएँ अक्सर चर्चा का विषय बनती हैं, तब यह और भी आवश्यक हो जाता है कि लोक सेवा के मूल आदर्शों को पुनः स्थापित किया जाए।

सिविल सेवाओं की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें विविधताओं से भरे इस विशाल देश में संतुलन बनाना होता है। एक ओर विकास की गति को बनाए रखना है, तो दूसरी ओर सामाजिक न्याय और समानता को भी सुनिश्चित करना है। यह कार्य आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक स्तरों पर निर्णय लेने होते हैं, जिनका प्रभाव लाखों लोगों के जीवन पर पड़ता है। आज तकनीक के युग में प्रशासनिक कार्यप्रणाली में भी बड़ा परिवर्तन आया है। डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएँ और पारदर्शी प्रक्रियाएँ—इन सभी ने नागरिकों और प्रशासन के बीच की दूरी को कम किया है। लेकिन तकनीक के साथ-साथ मानवीय संवेदना भी उतनी ही आवश्यक है। एक संवेदनशील अधिकारी ही वास्तविक अर्थों में जनसेवा कर सकता है। लोक सेवा दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रशासन केवल नियमों का पालन कराने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और न्याय की भावना स्थापित करने का एक सशक्त उपकरण है। जब नागरिकों को यह विश्वास होता है कि उनकी समस्याएँ सुनी जाएँगी और उनका समाधान होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। इसके साथ ही, यह दिन प्रशासनिक सुधारों और नवाचारों को प्रोत्साहित करने का भी अवसर है।

विचार

राशन कार्ड, नियमों की असमानता और लोकतंत्र की नैतिक

सुरेश सिंह

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में राशन कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों गरीबों के जीवन का सहारा है। यह भूख और गरिमा के बीच की वह पतली रेखा है, जो राज्य की संवेदनशीलता को परिभाषित करती है। परंतु जब मोटरसाइकिल रखने जैसे मानकों के आधार पर गरीबों के अधिकारों पर प्रश्नचिह्न लगने लगें और दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों को निरंतर सुविधाएं मिलती रहें, तब यह प्रश्न केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि न्याय, समानता और नैतिकता का बन जाता है।

1. पात्रता का प्रश्नः गरीबी की परिभाषा या प्रशासनिक सुविधा? हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में राशन कार्ड की सत्यापन प्रक्रिया तेज हुई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं अधिक जटिल है। कई मामलों में ऐसे लोगों को भी अपात्र घोषित कर दिया गया, जिनके पास मामूली संपत्ति जैसे एक पुरानी मोटरसाइकिल—होती है।

यहां मूल प्रश्न उठता है- क्या मोटरसाइकिल होना = सम्पन्न होता है ? भारत के ग्रामीण और अर्धशहरी परिवेश में मोटरसाइकिल आज विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता है, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का साधन। ऐसे में इसे समृद्धि का प्रतीक मानकर गरीबों को योजनाओं से बाहर करना न केवल तर्कहीन है, बल्कि सामाजिक वास्तविकताओं से कटे हुए निर्णय का उदाहरण भी है।

2. दोहरे मानदंडः इस विषय पर उठाया गया सबसे गंभीर सवाल यही है कि जहां आम नागरिकों के लिए कठोर पात्रता मानक लागू किए जाते हैं, वहीं जनप्रतिनिधियों और उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए अलग व्यवस्था दिखाई देती है। एक ओर गरीब परिवार को छोटी सी संपत्ति के कारण योजनाओं से बाहर किया जाता है। दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों को पद पर हों या न हों, पेंशन और सुविधाएं निरंतर मिलती रहती हैं।यह स्थिति लोकतंत्र के मूल सिद्धांत समानता के विरुद्ध है।यदि एक वर्ग के लिए नियम कठोर और दूसरे के लिए लचीले हों, तो यह कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को खोखला कर देता है।

3.पारदर्शिता बनाम संवेदनशीलताः संतुलन का संकट। सरकारों का तर्क है कि राशन प्रणाली में फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को हटाना जरूरी है, ताकि संसाधनों का दुरुपयोग न हो। कई राज्यों में हजारों राशन कार्ड इसी प्रक्रिया में रद्द किए गए हैं। यह कदम सिद्धांततः सही है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब यह प्रक्रिया संवेदनहीन और यांत्रिक बन जाती है। डेटा आधारित जांच में त्रुटियां, गलत आय या संपत्ति का रिकॉर्ड, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की अनदेखी, इन कारणों से वास्तविक जरूरतमंद भी प्रभावित हो जाते हैं। स्वयं अधिकारियों और संगठनों ने भी स्वीकार किया है कि केवल कागजी आंकड़ों के आधार पर पात्रता तय करना उचित नहीं है।

4. सामाजिक न्याय की कसौटी पर नीतिःभारत का संविधान सामाजिक न्याय को राज्य की आधारशिला मानता है। ऐसे में किसी भी नीति का मूल्यांकन केवल प्रशासनिक दक्षता से नहीं, बल्कि इन प्रश्नों से होना चाहिए- क्या यह नीति कमजोर वर्गों को और कमजोर कर रही है क्या इसमें मानवीय दृष्टिकोण है क्या नियम सभी पर समान रूप से लागू हो रहे हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो नीति में सुधार आवश्यक है।

5. समाधान की दिशाः समानता आधारित नीति-निर्माण, इस पूरे विमर्श का निष्कर्ष नकारात्मक नहीं, बल्कि सुधार की दिशा में होना चाहिए। कुछ आवश्यक कदम-

(1) यथार्थवादी पात्रता मानक
गरीबी की परिभाषा को वर्तमान सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में पुनः परिभाषित किया जाए।

(2) मानवीय सत्यापन प्रक्रिया केवल डेटा नहीं, बल्कि मैदानी जांच और सामाजिक स्थिति को भी महत्व दिया जाए।

(3) सभी के लिए समान नियम जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के लिए एक समान नैतिक मानक स्थापित किए जाएं।

(4) अपील और पुनर्विचार का अधिकार। यदि किसी का राशन कार्ड निरस्त होता है, तो उसे न्यायपूर्ण अपील का अवसर मिलना चाहिये। राशन कार्ड केवल अनाज का अधिकार नहीं, बल्कि राज्य और नागरिक के बीच विश्वास का प्रतीक है।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआई: DELHIN / 2006 / 19302

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन बालाजी हाउस, 244, ब्लॉक- बी, लेन- 3, राकेश भारद्वाज चौक के नजदीक, दिल्ली - 110033 से प्रकाशित एवं मारुतिनंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, शक्ति कॉम्प्लेक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110042 से मुद्रित।

संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी
समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)
मेट्रो संपादक : दीपचंद्र कांडपाल (8447314925)

‘एक्शन इंडिया’ में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक केवल पीआरबी एक्ट के तहत ही उत्तरदायी। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

आलेख

पेंशन की विसंगति और नैतिकता का प्रश्न

हाल के वर्षों में देश के भीतर राजनीतिज्ञों को मिलने वाली पेंशन और सुविधाओं को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी है। यह विमर्श केवल वित्तीय घाटे का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और नैतिक समानता का है। एक ओर जहाँ 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई, वहीं दूसरी ओर सांसदों और विधायकों के लिए 'एक दिन का कार्यकाल' भी आजीवन पेंशन की पात्रता सुनिश्चित कर देता है। यह विरोधाभास लोकतंत्र की उस भावना पर चोट करता है जहाँ जनप्रतिनिधि को 'प्रथम सेवक' माना गया है। राजनीतिज्ञों और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली के बीच की खाई को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

पात्रता की अवधिः एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन का पात्र बनने के लिए कम से कम 10 से 20 वर्ष की निरंतर सेवा देनी होती है। इसके विपरीत, कई राज्यों में यदि कोई व्यक्ति केवल एक दिन के लिए भी विधायक बनता है, तो वह जीवनभर के लिए पेंशन का हकदार हो जाता है। पेंशन पर पेंशन सबसे विवादित पक्ष यह है कि यदि कोई व्यक्ति अलग-अलग समय पर विधायक, सांसद और मंत्री रहा है, तो कई मामलों में उसे हर पद की अलग-अलग पेंशन मिलती है। पंजाब जैसे राज्यों ने हाल ही में 'एक विधायक-एक पेंशन' का नियम लागू कर इस दिशा में सुधार की पहल की है, जो स्वागत योग्य है।

राजनीति को संवैधानिक रूप से 'सेवा' माना गया है, न कि 'आजीविका'। जब सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के तहत बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया है, तो 'सेवकों' के लिए राजकोष से विशेष प्रावधान करना दोहरे मापदंड जैसा प्रतीत होता है । भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाने की निरंतर आवश्यकता है, वहां पूर्व जनप्रतिनिधियों के भत्तों और पेंशन पर करोड़ों रुपये खर्च करना जनता की नजर में खलता है। आम नागरिक का यह तर्क तार्किक जान पड़ता है कि यदि देश की आर्थिक स्थिति पुरानी पेंशन देने की नहीं है, तो यह नियम सबसे पहले नीति-निमार्ताओं (सांसदों/विधायकों) पर लागू होना चाहिए।

अंक, अपेक्षा और अधूरा जीवन; एक सच्चाई

समाज के सामने कभी-कभी ऐसी खबरें (टीप :- कानपुर के समीप रतनपुर में पढ़ने वाली छात्रा का दसवीं की परीक्षा में अपेक्षा से कम अंक आने पर आत्महत्या) आती हैं जो केवल सूचना नहीं होतीं, बल्कि एक आईना बनकर हमारी सामूहिक सोच, प्राथमिकताओं और संवेदनाओं की पोल खोल देती हैं। एक 16 वर्षीय छात्रा द्वारा केवल अपेक्षा से कुछ कम अंक आने पर जीवन समाप्त कर लेना, किसी एक परिवार की त्रासदी भर नहीं है.....यह हमारे पूरे शिक्षा तंत्र, पारिवारिक दबाव और सामाजिक मानसिकता की विफलता का जीवंत प्रमाण है। 95% की चाह और 92% का परिणाम। यह अंतर केवल तीन अंकों का है, परंतु इसी तीन अंकों ने एक जिंदगी की पूरी संभावनाओं को निगल लिया। प्रश्न यह नहीं कि उस बच्ची ने ऐसा कदम क्यों उठाया; असली प्रश्न यह है कि हम उसे उस मानसिक स्थिति तक पहुंचने से रोक क्यों नहीं पाए? आज का शैक्षिक वातावरण अंक-केन्द्रित हो गया है, जहाँ ज्ञान की गहराई से अधिक महत्व प्रतिशत के आंकड़ों को दिया जा रहा है। बच्चे अब सीखने के लिए नहीं, बल्कि टॉप करने के लिए पढ़ते हैं। माता-पिता की अपेक्षाएं, समाज की तुलना और प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ ये सब मिलकर बच्चों के कोमल मन पर एक अदृश्य दबाव बनाते हैं, जो कई बार असहनीय हो जाता है। यह विडंबना ही है कि जिस उम्र में बच्चों को असफलताओं से सीखने और जीवन के उतार-चढ़ाव को समझने की जरूरत होती है, उसी उम्र में वे पूर्णता के बोझ तले दबकर टूट जाते हैं। हम उन्हें यह सिखाने में असफल रहे हैं कि जीवन एक परीक्षा के परिणाम से कहीं बड़ा है, और असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरूआत का अवसर है। इस घटना का सबसे पीड़ादायक पहलू यह है कि उस छात्रा ने अपने साथियों को पहले ही अपनी निराशा का संकेत दिया था। इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं संवाद का अभाव था- कोई ऐसा नहीं था जिससे वह खुलकर अपने मन की बात कह पाती। यह हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की उस दूरी को उजागर करता है।

न्यूज फ्लैश

मेडिएशन फॉर द नेशन एवं हरियाणा सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम पर जागरूकता शिविर आयोजित

राईः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत के तत्वावधान में मेडिएशन फॉर द नेशन एवं हरियाणा सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम के अंतर्गत एक जागरूकता शिविर का आयोजन दिनांक 20अप्रैल, 2026 गांव नसीरपुर बांगर, ब्लॉक राई, जिला सोनीपत में किया गया। यह शिविर सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के आदेशानुसार तथा श्री प्रचेता सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर चैतन्य, पैनल अधिवक्ता तथा सुश्री सुनीता, सामुदायिक मध्यस्थ द्वारा उपस्थि लोगों को मध्यस्थता (मेडिएशन) के महत्व एवं उसके लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता एक सरल, सस्ता एवं त्वरित विवाद निवारण का माध्यम है, जिससे आपसी सहमति के आधार पर विवादों का समाधान किया जा सकता है और न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है। इसके अतिरिक्त, पैनल अधिवक्ता श्री चैतन्य तथा श्री सोहैल, जिला समाज कल्याण ऑफिस से आमजन को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं एवं संशोधित योजनाओं सहित के बारे में भी जागरूक किया गया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, भरण-पोषण के प्रावधानों तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान लोगों को हरियाणा सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम के तहत उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। साथ ही, यह बताया गया कि किस प्रकार आमजन अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं छोटे-मोटे विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझा सकते हैं। इस जागरूकता शिविर में लगभग 40 लोगों ने भाग लिया और कार्यक्रम का लाभ उठाया। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज में शांति एवं सौहार्द बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया।

हरियाणा अध्यापक संघ व सर्व कर्मचारी संघ की हुई संयुक्त बैठक

लाड़वा 20 अप्रैल (विजय कौशिक) : लाडवा के खण्ड शिक्षा कार्यालय में आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ व सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक इकाई लाडवा द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी ऋषिपाल पाल भारद्वाज से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मीटिंग की गई जिसमें ब्लॉक प्रधान सुरेंद्र सैनी व जिला प्रधान वीरेंद्र सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी को स्कूल व अध्यापकों से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। सभी बातों पर विचार विमर्श के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ऋषिपाल भारद्वाज ने संघ को आश्वासन दिया कि अध्यापकों को कार्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी वह यह भी कहा कि आप अध्यापक भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रयास करें ।वह बच्चों का स्कूलों में अधिक से अधिक दाखिला करवाए । हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी ऋषिपाल भारद्वाज को सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने में पूरा प्रयास किया जाएगा। इस मीटिंग में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रधान सुरेंद्र सैनी ,जिला प्रधान वीरेंद्र सिंह रोडान,ब्लॉक सेक्रेटरी तिलक राज सलूजा ब्लॉक कैशियर राजबीर जिला सेक्रेटरी सुदर्शन ,जिला उप प्रधान नरेश कुमार पर अन्य संघ सदस्य बलवान ,धर्मवीर लालर ,विनोद ,राजेंद्र उपस्थित रहे

मंडी गेट बंद कर किसानों का धरना, बायोमेट्रिक सत्यापन का विरोध

प्रदर्शन

किसानों ने मार्किट कमेटी कार्यालय करनाल के गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया।

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। प्रदेश की मंडियों में बायोमेट्रिक सत्यापन और नए नियमों के विरोध में किसानों ने सोमवार को मार्किट कमेटी कार्यालय करनाल के गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस प्रदर्शन में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुरानी व्यवस्था के अनुसार फसल खरीद की मांग उठाई। किसानों का कहना है कि नए नियमों के कारण उन्हें अपनी फसल बेचने में भारी परेशानी हो रही है।

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल सहित पूरे हरियाणा की मंडियों में किसानों ने मार्किट कमेटी कार्यालयों के गेट बंद कर दिए और बाहर बैठकर धरना दिया। किसानों ने कहा कि पहले की तरह बिना किसी जटिल प्रक्रिया के फसल की खरीद होनी चाहिए, ताकि उन्हें मंडी में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता सुरेंद्र सागवान ने बताया कि सरकार और प्रशासन को पहले भी कई बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है। 11 अप्रैल को भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रोड जाम किया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया।

सुरेंद्र सागवान ने कहा कि सरकार इस बार मंडियों में तीन नए कानून लेकर आई है, जो पूरी तरह किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों पर सख्ती करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सरकार को उनकी समस्याओं को समझना चाहिए।

धरने पर बैठे किसानों ने सरकार से मांग की कि जिस तरह पहले मंडियों में फसल खरीदी जाती थी, उसी व्यवस्था को दोबारा लागू किया जाए।

किसानों ने कहा कि पहले भी मंडियां थीं और किसान आसानी से अपनी फसल बेचते थे, लेकिन इस बार गेहूं बेचने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों का एडीजीपी करनाल रेंज ने किया निरीक्षण

टीम एक्शन इंडिया
कमल मिड्ढा

करनाल। आज अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक करनाल रेंज डा. एम. रवि किरण द्वारा जिला पुलिस लाइन में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक करनाल नरेंद्र बिजारणिया तथा पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार भी मौजूद रहे।निरीक्षण के दौरान करनाल जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए विभिन्न मादक पदार्थों जैसे चूरापोस्त, गांजा, चरस, स्मैक, सुल्फा, सिरप, कैप्सूल, नशीली गोलियां, अफीम मिक्सचर, इनटॉक्सिकेंट पाउडर व हेरोइन आदि को मालखाना रजिस्टर के अनुसार चेक किया गया।

जिला पुलिस करनाल द्वारा अप्रैल 2026 तक न्यायालय से फैसला हो चुके कुल 88 मामलों में 390 किलोग्राम 524 ग्राम 150 मिलीग्राम मादक पदार्थ, 480 कैप्सूल तथा 28,387 नशीली गोलियां शामिल हैं। इन सभी जब्त मादक पदार्थों का बारीकी से निरीक्षण किया गया।

एडीजीपी के निर्देशन में तथा ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में इन मादक पदार्थों को जिला पुलिस लाइन करनाल में सुरक्षित स्थान पर सील कर दिया गया। एडीजीपी ने निर्देश दिए कि कमेटी की निगरानी में शीघ्र ही इन मादक पदार्थों का नियमानुसार निपटान बजीदा स्थित वेस्टेज फैक्ट्री में किया जाएगा।

रोहित सिंगला को बनाया गया अग्रवाल वैश्य समाज की युवा इकाई का राज्य सचिव

लाडवा, 20 अप्रैल (विजय कौशिक) : अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने लाडवा के रोहित सिंगला द्वारा किये जा रहे सामाजिक व धार्मिक कार्यों की बहुत सराहना करते हुए कहा कि रोहित सिंगला लम्बे समय समाज की सेवा में लगे हुए हैं। रोहित सिंगला के कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए युवा इकाई का राज्य सचिव बनाया गया है। रोहित सिंगला ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वह पूरी लग्न और ईमानदारी से निभाउंगा और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला का धन्यवाद करता हूं।

5.2 लाख बच्चों को मिलेगी मुफ्त दवा : डा. आनंद कुमार शर्मा

अभियान

21 अप्रैल और 5 मई को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल कृमि संक्रमण से होगा बचाव

टीम एक्शन इंडिया
कमल मिड्ढा

करनाल। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 21 अप्रैल और 5 मई को बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली जरूर खिलाई जाए। उन्होंने कहा कि यह दवा पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावशाली है और इससे बच्चों को कृमि रोग से बचाया जा सकता है।

डीसी शर्मा ने सभी विभागों से समन्वय बनाकर अभियान को सफल बनाने को कहा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली दवा बच्चों को अवश्य दिलवाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रह सके।

सिविल सर्जन डॉ. पूनम चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत 21 अप्रैल को जिले के एक से 19 वर्ष तक के लगभग 5.2 लाख बच्चों को सरकारी, निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल की गोली मुफ्त खिलाई जाएगी। इसके अलावा 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाएं, जो गर्भवती नहीं हैं और स्तनपान नहीं करा रहीं, उन्हें भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो बच्चे 21 अप्रैल को किसी कारण से दवा लेने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें 5 मई को मॉप-अप राउंड में गोली खिलाई जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा इस अभियान से छूट न जाए।

दो नशा तस्करों को पीछा कर किया गिरफ्तार

टीम एक्शन इंडिया
कमल मिड्ढा

करनाल। जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की करनाल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड कर आरोपियों के कब्जे से 2 किलो 960 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।

यूनिट प्रभारी इंस्पेक्टर ऋषिपाल कुमार ने बताया कि एएसआई उपकार को सूचना मिली थी कि मन्नु पुत्र रमेश यादव और कृष्ण पुत्र शंकर पासवान तरावड़ी में गुरुद्वारा के पास दादा खेड़े के सामने गली में गांजा बेचने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत रेड कर दोनों आरोपियों को मौके से काबू कर लिया।

तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से कुल 2 किलो 960 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मन्नु निवासी खेड़ा थाना सोरवाला जिला सारसा बिहार, वर्तमान पता तरावड़ी और कृष्ण निवासी शेखपुरा थाना नाकोठी जिला बेगुसराय बिहार, हाल गणेश फूड सौकड़ा रोड तरावड़ी के रूप में हुई है।

जिला परिषद वार्ड नंबर 10 व तरावड़ी वार्ड 8 के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू

टीम एक्शन इंडिया
कमल मिड्ढा

करनाल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि जिला परिषद वार्ड नंबर 10 और नगर पालिका तरावड़ी वार्ड नंबर 8 के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हो गई है। जिला परिषद वार्ड नंबर 10 के उपचुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त न्यायालय में 21 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसी प्रकार से तरावड़ी वार्ड नंबर 8 के उपचुनाव के लिए नीलोखेड़ी एसडीएम न्यायालय में 21 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नगरपालिका तरावड़ी वार्ड नंबर 10 के उपचुनाव के लिए एसडीएम नीलोखेड़ी को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। नामांकन पत्रों की जांच 27 अप्रैल को की जाएगी और उम्मीदवार 28 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिसके तुरंत बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे।उन्होंने बताया कि उक्त पदों के लिए मतदान 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। नगर निकायों के मतों की गणना 13 मई को सुबह 8 बजे से निर्धारित केंद्रों पर शुरू होगी, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद या आवश्यकतानुसार 12 मई को पुनर्मतदान की स्थिति में संपन्न की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में पंच, सरपंच और सदस्य पद के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का 10वीं पास होना आवश्यक है, जबकि महिलाओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास की योग्यता तय की गई है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति की उन महिला उम्मीदवारों के लिए, जो पंच (सदस्य ग्राम पंचायत), नगर परिषद-पालिका एवं निगम की सदस्य का चुनाव लड?ा चाहती हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त चुनाव लड? वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा भी तय की गई है, जिसमें जिला परिषद सदस्य के लिए 6 लाख रुपये रखी गई है।

समाज द्वारा दिए गए सम्मान व स्नेह से मिलेगी नई उर्जाः प्रवीण लाठर

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। शहर के जाटों गेट स्थित जाट चौपाल में जाट पंचायत एवं जाट मोहल्ला द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर के सम्मान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जाट समाज द्वारा जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया।

जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर ने कहा कि समाज द्वारा मुझे दिया गया स्नेह, मान-सम्मान एवं आशीर्वाद मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। इसके लिए मैं आप सभी का तहेदिल से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और समाज द्वारा मुझे जो पगड़ी पहनाई गई है, वह सब आपके प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास का प्रतीक है। इससे मुझे नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने समाज के सभी गणमान्य लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप द्वारा मुझे पहनाई पगड़ी की आन बान शान रखते हुए समाज द्वारा जो भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी, उसे पूरी इमानदारी एवं निष्ठा से पूरा करने का प्रयास करुंगा। इस अवसर पर करनाल के विधायक जगमोहन आंनद, नगर निगम महापौर रेनू बाला गुप्ता, पूर्व प्रधान जोगिंदर लाठर, प्रधान मेहताब सिंह, पार्षद प्रियंका मित्तू सैनी, मनोनीत पार्षद गौरव नागपाल एवं नागरिक एवं परिवारजन उपस्थित रहे।

अवैध हथियार सप्लायर गिरफ्तार, खरीदने वाला पहले पकड़ा जा चुका

टीम एक्शन इंडिया
कमल मिड्ढा

करनाल। जिले में अवैध हथियार तस्करी के मामले में पुलिस की सीआईए-2 की टीम ने एक आरोपी गांव गौंदर निवासी बलविंदर सिंह पुत्र महिंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे पूछताछ के आधार पर पकड़ा। जांच अधिकारी के अनुसार इस मामले में पहले आरोपी प्रदीप पुत्र सुभाष निवासी बाल्मीकि बस्ती निसिंग को अवैध देसी पिस्तौल .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान प्रदीप ने बताया कि उसने यह हथियार बलविंदर से खरीदा था।

फैमिली आईडी में मुस्लिम महिला का पति हिंदू दिखाया

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। जिले में फैमिली आईडी में बुजुर्ग मुस्लिम महिला का पति हिंदू दिखा दिया गया। 70 साल की मुस्लिम महिला के पति की मौत करीब 20 साल पहले हो चुकी है। लेकिन गलत एंट्री के कारण उसका राशन कार्ड काट दिया गया।

महिला ने बताया कि गलत नाम जुड? की वजह से उसका राशन कार्ड करीब 11 महीने पहले कट गया। पहले वह सरकारी राशन से अपना घर चला रही थी, लेकिन अब उसे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजारे के लिए उसने एक गाय पाल रखी है और उसका दूध बेचकर किसी तरह घर चला रही है। उधर अधिकारियों का कहना है कि मामला जांच के अधीन है और जल्द ही लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर एक्शन होगा और महिला की समस्या का समाधान किया जाएगा।

दरअसल मामला करनाल के चांद सराए कॉलोनी का है। 70 वर्षीय रहीसा ने बताया कि उसके पति नसीर का निधन करीब 20 साल पहले हो चुका है। इसके बावजूद उसकी फैमिली आईडी में रणधीर नाम के व्यक्ति को उसका पति दिखा दिया गया है। रहीसा का कहना है कि वह मुस्लिम है, जबकि रणधीर हिंदू है और वह इस व्यक्ति को जानती तक नहीं है। इस तरह की विभागीय लापरवाही के चलते अब उसे परेशानियां उठानी पड़ रही है।

बुजुर्ग महिला ने बताया कि वह इस गलती को ठीक करवाने के लिए कई दफ्तरों के चक्कर काट चुकी है। पहले वह एडीसी दफ्तर गई, जहां से उसे बिजली दफ्तर भेज दिया गया। वहां से अटल सेवा केंद्र भेजा गया, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया।

रहीसा की बेटी सानिया ने भी कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन फैमिली आईडी में गड़बड़ी के कारण उसके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। महिला ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उसकी फैमिली आईडी की गलती को ठीक किया जाए, ताकि उसे राशन और अन्य सरकारी सुविधाएं मिल सकें।

एडीसी डॉ राहुल ने बताया कि ये ममला अभी उनके संज्ञान में नहीं था, अभी मामला सज्ञांन में आया है। कल बुजुर्ग महिला को अपने कार्यालय में बुलाकर उनकी इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे।

विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम कियाः रीना

बाबैन, 20 अप्रैल (विजय कौशिक) : देश में नारी सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध करने पर कांग्रेस एवं उसके सहयोगी विपक्षी दलों पर भाजपा महिला मोर्चा जिला कुरुक्षेत्र की महामंत्री रीना सैनी ने महिलाओं के हितों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों और महिला वर्ग में भी नाराजगी साफ देखी जा रही है। भाजपा महिला मोर्चा जिला कुरुक्षेत्र की महामंत्री रीना सैनी ने कहा कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल संसद में गिरा कर महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल समय की मांग थी लेकिन कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल को संसद में रोक कर अपना महिला विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही महिलाओं को आरक्षण दिलाने के नाम पर केवल दिखावा किया है। रीना सैनी ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, ऐसे में इसका विरोध करना महिलाओं के अधिकारों का हनन है। उनका कहना है कि इस तरह के संवेदनशील विषय पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुटता दिखानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हित सर्वोपरि होने चाहिए और किसी भी राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर सभी विपक्षी दलों को भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने महिलाओं को आह्वान किया कि वे एकजुट होकर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों का सबक सिखाने का काम करे ताकि भविष्य में कोई भी विपक्षी दल महिलाओं के हितों पर कुठाराघात करने का दुस्साहस ना कर सके। इस अवसर पर सीएम एमिनेंट पर्सन चंद्रकांता, रोशनी देवी, नेहा सैनी, नीलम देवी, ममता, कविता देवी के अलावा अनेक महिलाएं उपस्थित रही।

सीजेएम ने ली हिट एंड रन मुकदमों के लिए गठित कमेटी की बैठक

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन ने सोमवार को जिला एडीआर सेंटर में हिट एंड रन मुकदमों के लिए गठित कमेटी की बैठक ली और हिट एंड रन मुकदमों की रिपोर्ट पर चर्चा की। सीजेएम ने रिपोर्ट के आधार पर सदस्यों का मार्गदर्शन किया, जिससे अधिकतम पीड़ितों व उनके परिवारों को समय पर सहायता प्राप्त हो सके।

बचपन बचाओ के अंतर्गत गठित कमेटी के साथ बैठक

इसके बाद सीजेएम ने बचपन बचाओ के अंतर्गत गठित कमेटी के साथ बैठक कर बच्चों के हित में सरकारी योजनाओं को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कमेटी के सदस्यों का मार्गदर्शन किया, जिससे किसी भी बच्चे के अधिकारों का हनन न हो सके।

न्यूज फ्लैश

जग ज्योति दरबार में महंत राजेंद्र पुरी के सान्निध्य में श्रद्धालुओं ने आयोजित किया सम्मान समारोह

टीम एक्शन इंडिया
धर्म सिंह जोगना खेड़ा

थानेसर : जग ज्योति दरबार में महंत राजेंद्र पुरी के सम्मान में सोमवार को श्रद्धालुओं द्वारा एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह गुरुओं की सेवा एवं अवतरण दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। महंत राजेंद्र पुरी का श्रद्धालुओं द्वारा फूल मालाओं एवं पुष्प वर्षा से सम्मान के उपरांत विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इस मौके पर हवन यज्ञ में भी आहुतियां दी गई। महंत राजेंद्र पुरी ने श्रद्धालुओं के प्रेम एवं सम्मान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा, असहायों के सहयोग एवं गौ सेवा को समर्पित किया हुआ है उन्होंने कहा कि सत्य ही सनातन है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो अनादि काल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा वह ही सनातन शाश्वत है। महंत राजेंद्र पुरी ने बताया कि सनातन संस्कृति में संस्कार का बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सोलह संस्कार का विधान बताया है, जिसमें उपनयन संस्कार प्रमुख है। युवाओं को सामाजिक कार्यो में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र व धर्म से बड़ा कोई नहीं है। हमें अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए अपने धर्म को भी सुरक्षित रखना होगा। आज देश में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। जरूरत है युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन की। राष्ट्र व धर्म के साथ-साथ गरीबों मदद होनी चाहिए। इस मौके पर अंगद कुमार, सरयांश सिंह, बलजिंद्र पाल, रघुवीर चौहान, नरेश कुमार, राजीव शर्मा, हरीश चंद, राहुल, अजय राठी, विजय राठी, अक्षय राठी व मनप्रीत सिंह इत्यादि भी मौजूद रहे।

जींद : नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की जेल

जींद। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त एवं सत्र न्यायधीश शिफा कि अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में दोषी को पांच वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता राजेश ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि चार अप्रैल 2024 को थाना सदर सफीदों में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें पीड़ित की नाबालिग पुत्री को गांव ऐंचराखुर्द निवासी गौरव बहला फुसला कर ले गया था।

फसल खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी, किसानों को नहीं आने दी जाएगी कोई परेशानी: अतिरिक्त मुख्य

अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार ने कालांवाली अनाज मंडी का किया निरीक्षण,

उठान

अभी तक किसानों की ओर से किसी प्रकार की परेशानी की शिकायत नहीं आई है

सिरसा, (रणबीर खटक)

अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार ने कहा कि मंडियों में गेहूं फसल की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। अभी तक किसानों की ओर से किसी प्रकार की परेशानी की शिकायत नहीं आई है। उठान कार्य भी जारी है और इसमें तेजी लाई जाएगी। सरकार किसानों की गेहूं की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए सफलतापूर्वक खरीद प्रक्रिया चला रही है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सोमवार को कालांवाली अनाज मंडी के निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल, एसडीएम कालांवाली मोहित कुमार सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंडियों में गेहूं की खरीद प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। अभी तक किसानों की ओर से किसी भी प्रकार की परेशानी या तकनीकी खामी की शिकायत नहीं मिली है। चाहे गेट पास काटने की प्रक्रिया हो या बायोमेट्रिक सत्यापन, सभी प्रणालियां सही ढंग से काम कर रही हैं। मीडिया की ओर से बायोमेट्रिक सत्यापन में दिक्कत बारे पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक के लिए तीन लोगों को अधिकृत किया गया है। इससे किसानों को सुविधा हुई है, क्योंकि वे अपने परिवार के किसी अन्य अधिकृत सदस्य को साथ लाकर भी बायोमेट्रिक करवा रहे हैं। इसलिए बायोमेट्रिक को लेकर अभी कोई दिक्कत नहीं है।

मंडी में आ रही आवक के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंडी में 90 प्रतिशत के करीब अनाज की आवक हो चुकी है। संबंधित खरीद एजेंसियों और अधिकारियों को उठान कार्य में तेजी लाए जाने बारे दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि मंडी में अनाज का ढेर न लगे, ताकि नए आने वाले किसानों को अपनी फसल रखने में कोई असुविधा न हो।

आढ़तियों व किसानों से किया संवाद

कालांवाली अनाजमंडी में निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार ने आढ़तियों, किसानों व ट्रांस्पोर्टर से बातचीत कर उनकी आवश्यकताएं जानी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान आढ़तियों व किसानों ने मंडी के साथ लगती सडक का लेवल उपर होने के कारण मंडी में बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या रखते हुए इसका जल्द हल करवाने की मांग रखी। इसके अलावा नई एडिशनल मंडी की चार दिवारी बनाने की भी मांग रखी ताकि मंडी में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो। साथ ही मंडी की आवश्यकता अनुसार सडकों की रिपेयर तथा फड़ की रिपेयर करवाने की भी मांग की जिस पर मौजूदा अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

उक्त सभी शिकायतों के उचित त्वरित समाधान

शिकायत

सभागार में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में कुल तीन शिकायत प्राप्त हुई

टीम एक्शन इंडिया

नरवाना: एसडीएम जगदीश चंद्र की अध्यक्षता में उपमंडल स्तर पर लगातार समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में कुल तीन शिकायत प्राप्त हुई। एसडीएम जगदीश चन्द्र ने बताया कि उक्त सभी शिकायतों के उचित त्वरित समाधान के लिए मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चन्द्र के अनुसार समाधान शिविर से लोगों को विशेष राहत मिल रही है कि उन्हें अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अलग-अलग दफ्तरों में चक्कर लगाने की बजाय सभी विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे और एक ही निश्चित समय अवधि में उपलब्ध हो रहे हैं। एसडीएम ने बताया कि समाधान शिविर प्रत्येक सोमवार एवं वीरवार को प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक निरंतर आयोजित किए जा रहे है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिविर का लाभ उठाएं।

उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि अपने विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा अपडेट रखें और समाधान की गई शिकायतों की रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करें। साथ ही ऐसी समस्या जिसका किंहीं कारणों से निदान नहीं हो पाया इसका ब्यौरा भी कारणों सहित प्रस्तुत करें। समाधान शिविर में बीडीपीओ तरुण सुथार, नायब तहसीलदार लेखा नरेश कुमार, पुलिस विभाग से एएसआई कुलदीप सिंह, सिंचाई विभाग से जेई विक्रम सिंह, जन स्वास्थ्य विभाग से एसडीओ कुलदीप कोहाड़ , नगर परिषद से जेई प्रदीप सिंह, वन विभाग से संदीप कुमार, बिजली विभाग से एसडीओ महेश कुमार व जेई अजय कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से एसडीओ सुनील कुमार, काढ़ा से जेई सुनील कुमार, मार्केट कमेटी सचिव रोशन लाल, तहसील कल्याण अधिकारी सन्तरो देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

विधिक सहायता प्रदान करने के लिए डीएलएसए ने स्थापित किए हेल्प डेस्क

टीम एक्शन इंडिया
दलबीर सिंह मलिक

कुरुक्षेत्र : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुरुक्षेत्र की सीजेएम एवं सचिव नीतिका भारद्वाज के निदेर्शानुसार एलएनजेपी अस्पताल और मिनी सचिवालय कुरुक्षेत्र में आयोजित समाधान शिविर में आम जनता को विधिक सहायता प्रदान करने हेतु डीएलएसए द्वारा एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।

सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने अवगत कराया कि यदि किसी भी व्यक्ति को समाधान शिविर के दौरान विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वे वहां उपस्थित डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता से संपर्क कर मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। डीएलएसए की ओर से पैनल अधिवक्ता सुप्रीत सिंह समाधान शिविर में आने वाले नागरिकों को विधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से डीएलएसए के पीएलवी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वृद्धावस्था पेंशन प्रमाण पत्र से संबंधित विधिक सहायता प्रदान की जा रही है।

शहरी शिक्षा समिति ने मेधावी छात्रों व शिक्षकों को किया सम्मानित

टीम एक्शन इंडिया
नरवाना, 20 राहुल

गांव सिंसर के राजकीय विद्यालय में राह ग्रुप फाउंडेशन एवं शहरी शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों तथा मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य वीरेंद्र मलिक ने की।

समारोह के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 4 मेधावी छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित भूमिका निभाने वाले 11 शिक्षकों को भी प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर गौरवान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त समाज सेवा में सक्रिय दो समाजसेवियों को भी सम्मानित कर उनकी सेवाओं को सराहा गया। प्राचार्य वीरेंद्र मलिक ने कहा कि शिक्षा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे सशक्त माध्यम है और ऐसे आयोजन विद्यार्थियों व शिक्षकों को नई ऊर्जा

प्रदान करते हैं। राह ग्रुप फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष राजेश टांक दनौदा ने विद्यार्थियों व युवाओं का आान करते हुए कहा कि संस्था का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाना है। उन्होंने विद्यार्थियों से जुलाई माह में प्रत्येक द्वारा पांच-पांच पौधे लगाने का संकल्प लेने की अपील की, ताकि पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय योगदान दिया जा सके।

फाउंडेशन के उपप्रधान डॉ. अमित सैन ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि एक साथ 11 शिक्षकों का सम्मानित होना उनके समर्पण, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि राह ग्रुप फाउंडेशन एवं शहरी शिक्षा समिति पिछले कई वर्षों से शिक्षा, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं। कार्यक्रम में मुख्य अध्यापक सीताराम, पूर्व एसएमसी सदस्य डॉ. सुरेश कुमार तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार रखते हुए इस पहल की सराहना की और विश्वास जताया कि ग्राम पंचायत एवं विद्यालय परिवार शिक्षा के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा।

समारोह के अंत में सभी सम्मानित प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन एवं सफल आयोजन प्राचार्य वीरेंद्र मलिक, डॉ. अमित सैन, राजेश टांक, मुख्याध्यापक सीताराम, डॉ. दलबीर सिंह, नत्थूराम, डॉ. सुरेश कुमार एवं पवन सिहाग के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

दाना-दाना कर के खरीद रही हरियाणा सरकार: संदीप दनौदा

टीम एक्शन इंडिया
नरवाना, राहुल

हरियाणा में अनाज खरीद को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। सर्वजातीय बिनैन खाप के प्रवक्ता संदीप दनौदा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों से दाना-दाना खरीदने की बजाय दाना-दाना करके खरीद रही है। संदीप दनौदा के मुताबिक प्रदेश की मंडियों में खरीद प्रक्रिया बेहद धीमी है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फसल समय पर नहीं उठाई जा रही और किसानों को बार-बार मंडियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। व खुले में पड़ी फसल खराब होने का खतरा बढ़ रहा है साथ में बायोमेट्रिक सिस्टम पर उठाए बड़े सवाल। दनौदा ने खास तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर भी सरकार को घेरा।उन्होंने कहा की हर ट्राली के साथ बायोमेट्रिक लगवाना किसानों के लिए बेहद मुश्किल है एक किसान बार-

बार लाइन में लगकर बायोमेट्रिक कैसे कराएगा। इससे खरीद प्रक्रिया और धीमी हो रही है छोटे और बुजुर्ग

साधा निशाना

किसानों की परेशानियों का खामियाजा हर सरकार को भुगतना पड़ा है

किसानों के लिए यह व्यवस्था और ज्यादा परेशानी पैदा कर रही है उनका कहना है कि तकनीक का इस्तेमाल किसानों की सुविधा के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें और परेशान करने के लिए। खाप प्रवक्ता संदीप दनौदा ने सरकार से सवाल किया की क्या यही किसानों के हित में बनाई गई नीति है। खरीद प्रक्रिया को आसान और तेज क्यों नहीं किया जा रहा। बायोमेट्रिक जैसी शर्तों से किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है। खाप प्रवक्ता संदीप दनौदा ने साफ शब्दो में कहा की किसानों की परेशानियों का खामियाजा हर सरकार को भुगतना पड़ा है और भविष्य के चुनावों में सरकार को भी भुगतना पड़ेगा।

बार कौंसिल के स्टे के बावजूद हुए नरवाना बार के चुनाव-आदित्य शर्मा

टीम एक्शन इंडिया
नरवाना, 20 राहुल

नरवाना बार एसोसिएशन में प्रधान पद का चुनाव एक बार फिर विवादों में आ चुका है। एडवोकेट आदित्य शर्मा ने बार एसोसिएशन के चुनाव को गलत बताते हुए रिटर्निंग अधिकारी कुलवंत श्योकंद व मनिन्न्द्र श्योकंद पर गलत चुनाव कराने का आरोप लगाया। इस मौके पर एडवोकेट आदित्य शर्मा ने कहा कि नरवाना बार के चुनावों को लेकर बार कौंसिल पंजाब एंड हरियाणा द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया था। तभी बतौर उम्मीदवार मैने बार एसोसिएशन नरवाना के चुनावों से स्वंय को अलग करके चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे द्वारा चुनाव का बहिष्कार किए जाने के बावजूद रिटर्निंग अधिकारी ने समाज में यह संदेश दिया कि आदित्य शर्मा को केवल 11 वोट मिले है जिससे समाज में मेरी छवि धूमिल हुई।

इस बारे जब रिटर्निंग अधिकारी कुलवंत श्योकंद से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया आदित्य शर्मा ने 12 अप्रैल को टैंडर वोट के लिफाफे की सील पर साईन किए हुए है तो 13 अप्रैल को चुनाव से एक दिन पहले वो बहिष्कार कैसे कर सकते है। इसके अलावा 3 अप्रैल को नामिनेशन वापस लेने की तिथि थी जिसमें भी आदित्य शर्मा ने नामांकन वापस नहीं लिया। उन्होंने बताया कि यह चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष एवं लीगल तौर पर करवाया गया है। उन्होंने कहा कि गत 30 मार्च 2026 को नरवाना बार चुनाव का शैडयूल जारी हो चुका था और 1 व 2 अप्रैल को नामांकन पत्र भरने की तिथि थी और 3 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की तारीख थी और 3 अप्रैल को ही सर्वसम्मति से सचिव व कोषाध्यक्ष बार द्वारा चुन लिए गए थे। प्रधान पद के लिए दो उम्मीदवार आदित्य व अनिल मोर के नामांकन आए थे। किसी भी उम्मदीवार ने 3 अप्रैल तक नामांकन वापस नहीं लिया। उन्होंने बताया कि एक बार चुनाव प्रोसैस शुरू होने के बाद स्टे मान्य नहीं रखता स्टे केवल कांउटिंग के लिए दिया जा सकता है। एडवोकेट आदित्य शर्मा ने कहा कि इस फैसले को लेकर बार कौंसिल ने आगामी 30 अप्रैल को तारीख मुकरर है जिसके बाद आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी।

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का हुआ सफल आयोजन

टीम एक्शन इंडिया
नरवाना, 20 राहुल

नरवाना स्थित के.एम. राजकीय महाविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की टैगोर लिटरेरी सोसायटी के तत्वावधान में एक ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. मीनू सिंह द्वारा किया गया।

इस अवसर पर प्राचार्या डॉ. मीनू सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का युग है, जिसमें आगे बढ़ने के लिए केवल पाठ्य ज्ञान ही नहीं बल्कि तर्कशक्ति, निर्णय

क्षमता और विषयों की व्यापक समझ अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करती हैं।

अंग्रेजी विभागाध्यक्ष श्री सज्जन कुमार ने कार्यक्रम के दौरान प्राचार्या को विभाग की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विभाग के छात्र-छात्राएं निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर महाविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं।

कार्यक्रम का कुशल संचालन टैगोर लिटरेरी सोसायटी की संयोजिका प्रोफेसर प्रमिला द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में कुल छह टीमों ने भाग लिया, जिनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। अंत में मानसी,

प्रतिभा

विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया

विजयलक्ष्मी और सविता की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर बाजी मारी। रवीना, महक और काफी की टीम द्वितीय स्थान पर रही, जबकि मानसी, रीना देवी और मनेहा की टीम ने तृतीय स्थान हासिल किया। इस आयोजन को सफल बनाने में अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक डॉ. सुरेंद्र सिंह, मुकेश रानी तथा प्रो. मोनिका का विशेष योगदान रहा।

नरवाना अनाज मंडी में किसानों का हल्ला बोल, 3 घंटे ठप रहा मार्केट कमेटी दफ्तर

टीम एक्शन इंडिया
नरवाना, 20 अप्रैल राहुल

नई अनाज मंडी नरवाना में संयुक्त किसान मोर्चे का धरना आज भी जारी रहा। यह धरना मास्टर बलबीर सिंह, राज्य अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के नेतृत्व में चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष बढ़नपुर ने की।

धरने के दौरान संयुक्त किसान मोर्चे के घटक संगठनों–अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन घासी राम, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान मजदूर यूनियन हरियाणा, संघर्ष मंच

हरियाणा आदि के कार्यकताओं ने संयुक्त रूप से मार्केट कमेटी सचिव कार्यालय को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रखा। इस कार्रवाई के माध्यम से मोर्चे के फैसले को सफल बनाया गया।

इस अवसर पर मास्टर बलबीर सिंह, जोगिंद्र सिंह राज्य अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन घासी राम, बलवान सिंह उझाना भारतीय किसान यूनियन टिकैत, सत्यवान जिला प्रधान, भारतीय किसान मजदूर यूनियन हरियाणा, सुरेश बदनपुर जनसंघर्ष मंच तथा सतबीर खरल ने मार्केट कमेटी गेट को तीन घंटे बंद रखने के निर्णय पर विस्तार से चर्चा की।

वक्ताओं ने अपने संबोधन में सरकार की बेरुखी, तानाशाही, जनविरोधी नीतियों और तुगलकी फरमानों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए जनता की एकजुटता बेहद जरूरी है, ताकि सरकार की गलत नीतियों का डटकर मुकाबला किया जा सके।

कार्यक्रम में डिम्पल, रामप्यारी, ओमपति, मास्टर बलजीत सिंह माण्डी, मास्टर सतबीर गलाडी, रामधारी सिंह ढाकल, राजेश ढाकल, ताला राम, रत्ना हथो , निहाल सिंह, सुरजन, मांगेराम, अलबेल सिंह, बलराज, रत्न सिंह, साधु राम, चंद्रभान, जयपाल सिंह, ओमप्रकाश, कुलवंत सिंह, इंद्र सिंह, सतपाल, लीलू, बलजिंद्र सिंह अम्बरसर, बदन सिंह, जोधा सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति

डीआरओ संजय कुमार ने समाधान शिविर में सुनी जनसमस्याएं

सिरसा, (रणबीर खटक)

स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में सोमवार को समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां डीआरओ संजय कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनीं। इसके अलावा उपमंडल स्तर पर भी समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार के निदेर्शानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला एवं उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

डीआरओ संजय कुमार ने उपस्थित विभागों को निर्देश दिए कि

विभागाध्यक्ष शिकायतों के निपटान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए गंभीरता से कार्य करें। इसके अलावा अपने कार्यालयों में आने वाली समस्याओं को भी तत्परता से निवारण करें। प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और उन्हें एक ही स्थान पर राहत मिले, यही समाधान शिविर का मुख्य उद्देश्य है। सरकार का उद्देश्य है कि आमजन की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान हो।

ब्लॉक की 8 पंचायतों में 9 वार्ड सदस्यों के लिए उपचुनाव की तैयारियां तेज, 10 मई को होगा मतदान

बैठक

शिक्षकों व विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की बैठक आयोजित कर दिशा-निर्देश दिए।

टीम एक्शन इंडिया

गन्नौर। ब्लॉक क्षेत्र की पंचायतों में वार्ड सदस्यों के उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को खंड कार्यालय में सहायक जितेश ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों व विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान सहायक जितेश ने बताया कि गन्नौर ब्लॉक की 8 पंचायतों में 9 वार्ड सदस्यों के लिए उपचुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी ड्यूटी को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाएं। जितेश ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी। इस दौरान नामांकन से जुड़े सभी कर्मचारी निर्धारित समय में नामांकन पत्र जमा करवाने का कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जबकि 28 अप्रैल को नामांकन वापसी की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद 10 मई को संबंधित मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कर्मचारियों को चुनाव संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए।गन्नौर में इन पंचायतों में होगा पंचायत सदस्य का चुनाव - पंचायत अधिकारी अमित ने बताया कि गन्नौर में गांव बाय, भाखरपुर, घसौली, गढ़ी झंझारा, गढ़ी गुलामा, तेवड़ी, पुरखास, सिटावली आदि पंचायतों में पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होगा।

टेट अनिवार्यता के खिलाफ विधायक देवेंद्र कादियान को सौंपा ज्ञापन

टीम एक्शन इंडिया

गन्नौर। टेट अनिवार्यता के विरोध में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से जुड़े शिक्षकों ने गन्नौर विधायक देवेंद्र कादियान को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला सचिव दिनेश छिक्कारा ने बताया कि केंद्र व हरियाणा सरकार 1 सितंबर 2025 के फैसले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिसमें दिसंबर 2027 तक सभी कार्यरत अध्यापकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले से नियमित अध्यापकों पर यह शर्त थोपना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर खुलकर बोलने की मांग की। विधायक देवेंद्र कादियान ने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। ज्ञापन में जिला प्रधान नरेंद्र चहल ने कहा कि 10 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त अध्यापकों पर टेट की शर्त लागू कर उन्हें बाहर करने की साजिश रची जा रही है। साथ ही उन्होंने सीसीएल अवकाश प्रक्रिया को जटिल बनाने और एलटीसी नियमों में बदलाव को भी कर्मचारियों के अधिकारों पर कुठाराघात बताया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार शिक्षकों के अधिकारों को कमजोर कर रही है। यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर जोगिंदर, देशराज, ओम प्रकाश मलिक, रोहतास, ओम प्रकाश हुड्डा व कुलदीप सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे।

न्यूज फ्लैश

एसडीएम ने मंडी में खरीद प्रक्रिया बारदाने की उपलब्धता,उठान कार्य का लिया जायजा

गन्नौर। अनाज मंडी में गेहूं खरीद सीजन के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सोमवार को एसडीएम ने मंडी का दौरा कर गेहूं उठान कार्य व भंडारण व्यवस्था को लेकर मंडी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों से बातचीत कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने मंडी में चल रही खरीद प्रक्रिया, बारदाने की उपलब्धता और उठान कार्य की गति का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने दी जाए और उनकी फसल का समय पर उठान सुनिश्चित किया जाए। मंडी में मौजूद आढ़तियों ने एसडीएम को बताया कि वेयरहाउस व हैफेड द्वारा गेहूं लिफ्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मंडी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। एसडीएम ने साफ-सफाई, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए।

दो लापता मासूम बच्चों को पुलिस ने सुरक्षित खोज निकाला

गन्नौर। थाना बड़ी के अंतर्गत एक गांव से गायब हुए दो मासूम बच्चों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुरक्षित खोज निकाला। पुलिस के अनुसार 19 अप्रैल को एक 11 वर्षीय लड़का और 9 वर्षीय लड़की घर से अचानक लापता हो गए थे। स्वजन द्वारा डायल-112 पर की गई शिकायत के माध्यम से थाना बड़ी में इसकी सूचना मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चों के परिवार के साथ मिलकर आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों बच्चों को गन्नौर फ्लाईओवर के नीचे से सुरक्षित ढूंढ लिया। इसके बाद बच्चों को मिशन मुस्कान के तहत उनके परिवार को सौंप दिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से परिवार ने राहत महसूस की और आभार व्यक्त किया।

तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मजदूर की मौत

गन्नौर। बड़ी औद्योगिक क्षेत्र के पास जीटी रोड पर तेज गति से आई बाइक की टक्कर से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने इसकी शिकायत थाना बड़ी में दी। पुलिस को दी शिकायत में करैनी, बाघराय, जिला प्रतापगढ, उत्तरप्रदेश की रहने वाले आरती ने बताया कि वह अपने पति लालचन्द्र के साथ बड़ी गांव में किराये पर रह रही थी। वह 18 अप्रैल को अपने पति के साथ ड्यूटी खत्म कर कमरे पर लौट रही थी। जब वे जीटी रोड पार कर रहे थे, तभी दिल्ली की ओर से तेज गति से आ रही बाइक ने लालचन्द्र को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिर गए। राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने लालचन्द्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महिला आरक्षण पर बीजेपी का विरोध सिर्फ दिखावा, केन्द्र सरकार की नीयत साफ नही- प्रदीप चौधरी

पंचकूला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कालका से पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीतिक दिखावा कर रही है। हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसे लागू करने को जनगणना और परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जोड़ दिया गया है, जिससे इसकी वास्तविक शुरूआत में देरी हो रही है।
प्रदीप चौधरी ने कहा कि यदि केंद्र सरकार की नीयत साफ होती, तो मौजूदा सीटों पर ही महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जा सकता था।

छोटी गढ़ी का राजकीय प्राइमरी स्कूल बदहाल, जर्जर भवन से खतरा

टीम एक्शन इंडिया

गन्नौर। गांव छोटी गढ़ी स्थित राजकीय प्राइमरी स्कूल की हालत बेहद खराब हो चुकी है, जिससे यहां पढ? वाले बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल का भवन जर्जर स्थिति में है और कई स्थानों पर दीवारों में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। स्कूल की चारदीवारी भी कई जगह से टूटी हुई है, जिसके कारण बाहरी लोगों और पशुओं का अंदर आना-जाना लगा रहता है। इसके अलावा स्कूल परिसर में जंगली घास उगी हुई है, जो सांप-बिच्छू जैसे जहरीले जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बना रही है। ऐसे में बच्चों के लिए यहां पढ़ाई करना खतरे से खाली नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार इस समस्या को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों में इसको लेकर रोष बना हुआ है और उन्होंने जल्द से जल्द स्कूल की मरम्मत व सफाई कराने की मांग की है।

- स्कूल में सफाई कर्मी नहीं

मुख्याध्यापिका विद्यावति ने बताया कि स्कूल में सफाई कर्मी तैनात नहीं है। कई बार उन्होंने गांव के लोगों से मदद से मैदान की सफाई करवाई है। अब फिर से घास बड़ी हो गई है। वहीं टूटी दीवार को लेकर उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र सौंपा है जल्द ही दिवार रिपेयर होने की उम्मीद है।

- चारदीवारी का एस्टिमेट बना

खंड शिक्षा अधिकारी सुरजीत घणघस का कहना है कि उन्हें स्कूल की स्थिति की जानकारी मिली है चार दिवारी का एस्टिमेट बन चुका है, उसकी भी रिपेयर करवा दी जाएगी।
मैदान की सफाई के लिए निर्देश दे दिए गए हैं।

सुधा भारद्वाज के कार्यालय में बधाई देने वालों का लगा रहा तांता

पंचकूला मैनपाल : कांग्रेस की ओर से मेयर पद की उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सुधा भारद्वाज के कार्यालय में सोमवार को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।
शहर के विभिन्न क्षेत्रों और कॉलोनियों से बड़ी संख्या में लोग उनके कार्यालय पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए अपना समर्थन जताया। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम चंद्र मोहन भी विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने सुधा भारद्वाज को टिकट मिलने पर बधाई दी।
कार्यालय में पहुंचे लोगों ने विश्वास जताया कि सुधा भारद्वाज शहर के विकास और जनसमस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाएंगी। कॉलोनीवासियों ने उन्हें समर्थन देने का आश्वासन देते हुए कहा कि इस बार शहर में बदलाव की आवश्यकता है और वे इसके लिए एकजुट हैं।
इस अवसर पर सुधा भारद्वाज ने सभी समर्थकों, कॉलोनीवासियों और शहरवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा उन पर जताया गया विश्वास उनके लिए जिम्मेदारी भी है और वे इस पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगी।
उन्होंने कहा कि पंचकूला शहर इस समय कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को दी है प्राथमिकता

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। जिला कांग्रेस कमेटी की शहरी ईकाई के अध्यक्ष पराग गाबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को प्राथमिकता दी है।
उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह यह गलत प्रचार कर रही है कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, बल्कि पार्टी का विरोध केवल परिसीमन को लेकर है।
उनका कहना था कि आरक्षण जनगणना के आधार पर दिया जाना चाहिए।
पराग गाबा सोमवार को महिला आरक्षण बिल को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन किया था और यदि 543 लोकसभा सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है तो पार्टी उसका समर्थन करेगी।
कांग्रेस नेत्री मोनिका डुमरा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में महिलाओं को पूरा सम्मान मिला है और पार्टी कभी भी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं रही। भाजपा जनता में झूठ और भ्रम फैला रही है कि कांग्रेस महिला आरक्षण के विरोध में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया है

हरविन्द्र कल्याण ने सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सोमवार को सेक्टर 6 में 2 करोड़ 94 लाख व सेक्टर 7 में एक करोड़ 92 लाख की लागत से ग्रीन बेल्ट के सौंदर्यीकरण के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व नगर निगम के सहयोग से किए जाने वाले निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।
उन्होंने बताया कि सौंदर्यीकरण के लिए ग्रीन बेल्ट में ग्रिल सहित चारदीवारी और फुटपाथ रास्ता बनाया जाएगा। इसमें यहां के निवासियों के लिए ओपन जिम, बच्चों के खेलने के लिए उपकरण, लोगों के बैठने के लिए बैंच, कूड़ादान, बारिश से बचने के लिए आश्रय आदि की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन बेल्ट में घास व पौधे भी लगाए जाएंगे। यह कार्य लगभग एक साल में पूरा कर लिया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सेक्टर 6 व 7 का क्षेत्र घरौंडा विधानसभा में आता है। पिछले साढ़े नौ सालों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए जो भी कार्य किए हैं, उन्हें यहां की जनता भुला नहीं पाएगी। उन्होंने सेक्टर 6 व 7 के आसपास की सभी कॉलोनियों को नियमित किया है। यहां यूनिवर्सिटी, रिंग रोड, नहरों व पुलों का निर्माण कराया गया है। यहां के स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। अब तो करनाल को नया सिविल अस्पताल मिलने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिला के सभी विधायक तत्परता से विकास कार्य कर रहे हैं। यह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हुआ है। अब करनाल में रैपिड मेट्रो परियोजना पर भी काम शुरू हो गया है। यहां के प्रवासी लोगों के लिए छठ पूजा के लिए भी व्यवस्था की गई है।

पुन्हाना में जेसीबी से हत्या करने वाले वारिस को हुई उम्रकैद

नूंह मेवात (लियाकत अली): जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने वर्ष 2021 के चर्चित हत्या मामलें में आरोपी वारिस को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की अदालत द्वारा को सुनाया गया। अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला 18 मार्च 2021 को थाना पुन्हाना में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है

बड़ी गांव की महिलाओं ने विधायक से लगाई न्याय की गुहार

जनता दरबार

- पात्र परिवार को मिलेगा सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ : विधायक देवेंद्र कादियान

टीम एक्शन इंडिया

गन्नौर। विधायक देवेंद्र कादियान ने सोमवार को अपने निजी कार्यालय में साप्ताहिक जनता दरबार लगाकर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस दरबार में बिजली, पानी, सड़क और व्यक्तिगत शिकातयों का अंबार लगा रहा। जनता दरबार में बड़ी गांव के बीपीएल परिवारों ने 119 प्लॉटों के मालिकाना हक को लेकर गुहार लगाई है। विधायक ने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा और नियमों के अनुसार प्लॉट उनके पास रहेंगे। वहीं, बीएसटी कॉलोनी के निवासी भी नोटिस मिलने के बाद राहत की उम्मीद लेकर पहुंचे। इधर, दतौली गांव के फेफड़ों के रोग से ग्रस्त संदीप को विधायक ने ऑपरेशन के लिए मदद का भरोसा दिया है।
विधायक देवेंद्र कादियान ने कहा, गन्नौर की जनता का विश्वास ही मेरी ताकत है। जनता दरबार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
शिक्षकों कीं मांग को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा। प्लॉटों का मामला हो या कॉलोनियों के नोटिस, मेरा प्रयास है कि किसी गरीब का घर न उजड़े। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए है कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी।

अधिकारी शिकायत का यथासंभव करें निपटारा: एसडीएम योगेश

टीम एक्शन इंडिया
दिनेश नौताना

महेंद्रगढ़। एसडीएम योगेश सैनी ने कहा कि अधिकारी समाधान शिविरों की लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र उचित निपटारा करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निदेर्शों पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर में एक ही छत के नीचे सभी विभागों से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। एसडीएम योगेश सैनी ने स्थानीय लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कार्यालय कोर्ट रूम में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में लोगों की जनसमस्याओं की सुनवाई की। एसडीएम ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग के अधिकारी समाधान शिविर में प्राप्त हो रही हर शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें। समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों के निपटारे की सरकार द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है तथा सप्ताह के हर शुक्रवार को इन शिकायत के निपटारे की समीक्षा की जाती है।

स्वास्थ्य के प्रति सजगता ही सबसे बड़ी सुरक्षा - डॉ. संतोष कुमार

टीम एक्शन इंडिया

लाडवा, 20 अप्रैल (विजय कौशिक) गत दिवस को स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय एवं जनहितकारी पहल के तहत संजय गांधी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, धनौरा-लाडवा में यूरोलॉजी विषयक मेगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल एवं भव्य आयोजन किया गया। लाडवा क्षेत्र में इस प्रकार का यह पहला व्यापक स्वास्थ्य शिविर रहा, जिसने स्थानीय नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति नई जागरूकता का संचार किया।
यह शिविर गुरु नानक गीता कैलाश मेमोरियल फाउंडेशन एवं विद्यालय प्रबंधन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों नागरिकों ने भाग लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया और स्वास्थ्य जांच करवाई।
इस अवसर पर पीजीआई चंडीगढ़ के यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं यूनिट-2 के प्रमुख डॉ. संतोष कुमार मुख्य अतिथि एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में उपस्थित रहे। उनके आगमन पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। यज्ञशाला में आयोजित हवन में मुख्य अतिथि द्वारा पूर्णाहुति दी गई, जिससे कार्यक्रम को आध्यात्मिक गरिमा भी प्राप्त हुई। उपस्थित अतिथियों ने संस्थापक प्रधान स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश गर्ग की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
अपने प्रेरणादायक और विशेषज्ञीय संबोधन में डॉ. संतोष कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में यूरोलॉजी संबंधी रोगों में तेजी से वृद्धि हो रही है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग समय पर जांच और उपचार नहीं करवा पाते। उन्होंने बताया कि बार-बार पेशाब आना, पेशाब में जलन, कमजोर धार, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, किडनी संबंधी समस्याएं तथा पेशाब का अनियंत्रण जैसे लक्षणों को नजरअंदाज करना गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है।उन्होंने विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह देते हुए कहा कि संतुलित आहार, पर्याप्त जल सेवन, नियमित व्यायाम तथा नशामुक्त जीवनशैली अपनाकर इन रोगों से प्रभावी बचाव संभव है। उन्होंने ह्यह्यरोकथाम इलाज से बेहतर हैह्लह्ल के सिद्धांत को अपनाने पर बल दिया।शिविर के दौरान आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिनमें यूरोफ्लो टेस्ट, पीएसए टेस्ट, ब्लड प्रेशर एवं ब्लड शुगर जांच शामिल रहीं।
साथ ही आवश्यक दवाइयों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। कई मरीजों को आगे की जांच एवं उपचार हेतु विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया गया।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर कार्यशाला

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल के कुलपति प्रो. सुरेश मल्होत्रा के दूरदर्शी नेतृत्व में छात्र कल्याण निदेशालय द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड? की रोकथाम विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटैक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रो. अनीता यादव ने विशेष तौर पर भाग लिया।
मुख्य वक्ता ने पॉश एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए यौन उत्पीड? के विभिन्न रूपों, मौखिक, गैर मौखिक और शारीरिक व्यवहार की व्याख्या करते हुए इनके मानसिक और सामाजिक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने प्रतिभागियों को शिकायत दर्ज कराने के लिए उपलब्ध सी-बॉक्स पोर्टल की जानकारी दी तथा पीड़ितों को न्याय और सहायता प्रदान करने में आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका को भी स्पष्ट किया। उन्होंने महिलाओं को बिना भय के ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया।
निदेशक छात्र कल्याण प्रो. रंजन गुप्ता ने शैक्षणिक संस्थानों और कार्य स्थलों पर सुरक्षित, सम्मानजनक तथा समावेशी वातावरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का निवास होता है। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा किसी भी संस्थान के मूल मूल्य होने चाहिएं। कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. उमा प्रजापति ने किया।

डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, पीजी, डीएनबी और फेलोशिप पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या बढ़ने से मेडिकल ट्रेनिंग का दायरा बढ़ेगा

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने और हेल्थकेयर सर्विस को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं संस्थानों में वर्ष 2026 के लिए स्नातकोत्तर (पीजी) और डीएनबी कोर्स और फेलोशिप पाठ्यक्रम में 108 अतिरिक्त सीटों का प्रस्ताव किया है। विभाग के इस महत्वपूर्ण पहल से दिल्ली में मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्पेशल हेल्थकेयर सर्विस को और ज्यादा मजबूती मिलेगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने वर्ष 2026 के लिए राजधानी दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं संस्थानों में पीजी (एमडी/एमएस) और डीएनबी कोर्स की सीटों की संख्या में 103 सीटें बढ़ाने की अनुशंसा की है। इसके तहत फेलोशिप पाठ्यक्रम के तहत 5 सीटों को भी स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार पीजी, डीएनबी और फेलोशिप के लिए कुल मिलाकर 108 सीटें प्रस्तावित हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार दिल्ली के अलग-अलग प्रमुख अस्पतालों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में(एमडी/एमएस) की 67 सीटें और डीएनबी की 36 सीटें प्रस्तावित की गई हैं।

तो वहीं, फेलोशिप पाठ्यक्रम के अंतर्गत 05 सीटें प्रस्तावित हैं। जिनमें से 3 सीटें गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल और 2 सीटें दिल्ली स्टेट कैंसर संस्थान के लिए प्रस्तावित हैं।

'भारत की आधी आबादी इस षड्यंत्र के लिए इन राजनीतिक दलों को कभी माफ नहीं करेगी'

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्लीः गत सप्ताह कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी सहित विभिन्न विपक्षी दलों के कुटिल षड्यंत्र के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम तीन चौथाई समर्थन ना जुटा पाने के कारण गिर गया जिसके चलते समाज के हर वर्ग की महिलाओं में रोष व्याप्त है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा के साथ दिल्ली की दो प्रसिद्ध वरिष्ठ शिक्षाविदों रमा शर्मा प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज एवं रूबी मिश्रा प्रिंसिपल भगिनी निवेदिता कॉलेज ने एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करके कांग्रेस,आम आदमी पार्टी एवं समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों की नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति नकारात्मक कुटिलता की निंदा की है और कहा है कि भारत की आधी आबादी इस षड्यंत्र के लिए इन राजनीतिक दलों को कभी माफ नहीं करेगी।

'महिला आरक्षण बिल की आड़ में गलत ढंग से परिसीमन करना चाहती है सरकार'

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्लीः पिछले एक सप्ताह से संसद के विशेष सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के गिरने पर सत्ता और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली कांग्रेस ने केंद्र सरकार को साफ कहा है कि यह महिलाओं के साथ धोखा नहीं, बल्कि परिसीमन की आड़ में चुनावी साजिश है। राहुल गांधी ने सदन में कहा था, यह बिल महिलाओं का नहीं बल्कि इलेक्टोरल मैप बदलने का है बिल है क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो सितंबर 2023 में ही पास हो चुका है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस

कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी जोर देकर कहा है कि कांग्रेस महिला आरक्षण की सबसे पुरानी हिमायती है। हम 33 प्रतिशत आरक्षण चाहते हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के, तुरंत लागू होना चाहिए। परिसीमन को जोड़कर दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होना चिंता का विषय है उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। इसी मामले पर करावल नगर कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम विपक्ष की सहमति से ही पास हुआ था।

वृक्षारोपण कर मनाया करियर विल के चेयरमैन राकेश यादव का जन्मदिन

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्लीः पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए करियर विल के चेयरमैन राकेश यादव का 44वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

इस विशेष अवसर पर किसी भव्य आयोजन के बजाय प्रकृति को उपहार देते हुए पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

परिजनों और शुभचिंतकों ने किया पौधारोपण

न्यू एरा पब्लिक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में राकेश यादव के माता-पिता, शीला एवं राजवीर और उनकी बेटी प्रगति ने स्वयं पौधे लगाकर इस दिन को यादगार बनाया।

इस मौके पर अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेन्द्र यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे।

31 पौधों के साथ हरियाली का संकल्प

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेन्द्र यादव ने बताया कि इस उपलक्ष्य में स्कूल परिसर और आस-पास के क्षेत्र में लगभग 31 पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि जन्मदिन जैसे व्यक्तिगत अवसरों को सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों से जोड़ना समाज के लिए एक प्रेरणादायक पहल है।

स्कूल स्टाफ ने दी बधाई

न्यू एरा पब्लिक स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों ने राकेश यादव को उनके जन्मदिन की बधाई दी और उनकी दीघार्यु की कामना की।

वजीरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ. महेन्द्र नागपाल का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्लीः वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉ. महेन्द्र नागपाल का जन्मदिन क्षेत्र में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों सहित भारी संख्या में स्थानीय निवासियों ने शिरकत की।

फूल-मालाओं से हुआ स्वागत

सुबह से ही डॉ. नागपाल के आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। उपस्थित लोगों ने उन्हें लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं।

सामाजिक और राजनीतिक दिग्गजों की उपस्थिति

कार्यक्रम में वजीरपुर क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के प्रमुख लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने डॉ. नागपाल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों और जनसेवा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। एक स्थानीय समर्थक ने बताया कि डॉ. महेन्द्र नागपाल जी का व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर जनहित को प्राथमिकता दी है।

सेवा कार्यों का आयोजन

जन्मदिन के अवसर पर कई स्थानों पर फल वितरण का भी आयोजन किया गया। डॉ. नागपाल ने इस स्नेह के लिए सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता का यही प्यार उन्हें सदैव समाज की सेवा करने की ऊर्जा देता है।

आरक्षण में एससी/एसटी एवं ओबीसी महिलाओं को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने की मांग तेज

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्लीः रोहिणी जिला कांग्रेस कमेटी (एससी/एसटी सेल) के चेयरमैन एम एल भास्कर ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वे महिला आरक्षण का पूरी मजबूती से समर्थन करते हैं, लेकिन यह आरक्षण तभी सार्थक माना जाएगा जब इसमें समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 33% महिला आरक्षण के अंदर एससी/एसटी एवं ओबीसी वर्ग की महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना बेहद जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो

यह न केवल इन वर्गों की महिलाओं के साथ अन्याय होगा, बल्कि सामाजिक न्याय की मूल भावना के भी खिलाफ होगा। एम एल भास्कर ने कहा कि देश में लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाएं दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, एक तरफ वे महिला होने के कारण भेदभाव झेलती हैं और दूसरी ओर अपने सामाजिक वर्ग के कारण उन्हें अवसरों से वंचित रखा जाता है। ऐसे में महिला आरक्षण के भीतर उनका हक सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि महिला आरक्षण कानून में स्पष्ट प्रावधान किए जाएं, जिनके तहत एससी/एसटी एवं ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित हो, ताकि आरक्षण का लाभ केवल सीमित वर्ग तक सिमट कर न रह जाए, बल्कि वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे।

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पअर्पित करते हुए पूर्व निगम पार्षद सरदार मान सिंह।

नरेलाः विश्व हिन्दू परिषद का शंखनादः 'दासता की दिल्ली नहीं, स्वाभिमान का इंद्रप्रस्थ चाहिए'

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्लीः देश की राजधानी का नाम बदलकर उसका प्राचीन नाम 'इंद्रप्रस्थ' रखने की मांग अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेती जा रही है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की इंद्रप्रस्थ प्रांत टोली ने इस मुहिम को लेकर चौतरफा अभियान छेड़ दिया है। विहिप का स्पष्ट तर्क है कि 'दिल्ली' नाम गुलामी के प्रतीक के समान है, जबकि 'इंद्रप्रस्थ' भारत के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। डिजिटल और जमीनी स्तर पर मुहिम इस अभियान को जन-जन तक पहुँचाने के लिए विहिप ने क्यूआर कोड जारी किया है,

जिसके माध्यम से ऑनलाइन पिटीशन पर लोगों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मांग को लेकर व्यापक लहर देखी जा रही है।

दिल्ली केवल व्यावसायिक नाम, इंद्रप्रस्थ हमारी आत्मा" विश्व हिंदू परिषद, इंद्रप्रस्थ प्रांत के उत्तरी विभाग सहमंत्री मनोज बंसल ने इस अभियान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दिल्ली महज एक व्यावसायिक नाम है जो हमें दासता की याद दिलाता है और वास्तविक इतिहास से दूर ले जाता है। इसके विपरीत, इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में पांडवों की राजधानी थी। यह नाम शहर को उसकी सांस्कृतिक जड़ों, धर्म और स्वाभिमान से जोड़ता है।

उन्होंने आगे कहा कि यह केवल नाम परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि अपनी पहचान और संकल्प की खातिर एकजुट होकर 'इंद्रप्रस्थ' नाम के लिए समर्थन दें।

नरेला में 'श्री जगन्नाथ मंदिर' का शंखनाद, भूमि पूजन के साथ निकली भव्य कलश यात्रा

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्लीः नरेला विधानसभा क्षेत्र की राजीव कॉलोनी रविवार को 'जय जगन्नाथ' के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर जय जगन्नाथ सेवा समिति के तत्वावधान में श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण के लिए विधि-विधान से भूमि पूजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ भाग लिया।

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रखी गई नींव

कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। मुख्य यजमानों ने मंदिर की नींव में चांदी का नाग-नागिन, पंचरत्न और सुपारी अर्पित कर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। मंत्रों की ध्वनि और धूप-दीप के सुगंधित वातावरण ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय कर दिया।

501 कलशों के साथ नगर भ्रमण

भूमि पूजन के पश्चात सुबह 9:30 बजे कंफर्ट जोन स्थित मंदिर स्थल से विशाल कलश यात्रा शुरू हुई। यात्रा में 501 महिलाएं केसरिया और लाल परिधानों में सिर पर कलश धारण कर चल रही थीं। बैंड-बाजे, ऊंट-घोड़े और भगवान जगन्नाथ की मनमोहक झांकी के पीछे चलते श्रद्धालु "जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतू में" के जयघोष कर रहे थे। जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्थानीय निवासियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया।

जय जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि भगवान जगन्नाथ सबके नाथ हैं। यहाँ जात-पात का कोई स्थान नहीं है, यह मंदिर सामाजिक समरसता का केंद्र बनेगा।

समरसता का संदेश और विशाल भंडारा

इस आयोजन में राजनीति, समाजसेवा और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कई गणमान्य लोग शामिल हुए।

क्षेत्रीय विधायक, पार्षद और आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने भी मंदिर निर्माण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

शाम तक चले विशाल भंडारे में लगभग 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

फायर कर्मचारी सरकार की हठधर्मिता के विरोध में प्रदेश के सभी विधायकों व मंत्रियों को देंगे ज्ञापन-गुलशन भारद्वाज

शहीदों को न्याय व कच्चे फायर कर्मचारियों को सर्जित फायर ऑपरेटरों के पदों पर मर्ज करने की माँगो के पत्र जारी होने पर ही हड़ताल होगी

नितिन सिंगला जगाधरी
यमुनानगर, 20 अप्रैल। हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन की 8 अप्रैल से जारी राज्यव्यापी हड़ताल सोमवार को 13वें दिन में प्रवेश कर गई। इंडस्ट्री एरिया स्थित मुख्य दमकल केंद्र पर चल रहे धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान विजेंद्र सिंह ने की, जबकि संचालन जिला सचिव रिंकू कुमार ने किया। धरने को सम्बोधित करने पहुँचे महासचिव गुलशन भारद्वाज ने सरकार पर मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया।राज्य कमेटी के निर्णय के तहत अब 22 से 25 अप्रैल तक प्रदेश भर

के कच्चे व पक्के दमकल कर्मचारी 90 विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद 27 अप्रैल से सभी मुख्य दमकल केंद्रों पर क्रमिक भूख हड़ताल की जाएगी। भारद्वाज ने बताया कि फायर कर्मचारियों का आंदोलन अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। फरीदाबाद में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कच्चे कर्मियों भवीचंद शर्मा और रणवीर सिंह को शहीद का दर्जा,आश्रितों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा,परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी,भविष्य के लिए स्थायी सुरक्षा नीति,रेगुलर कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रांसफर पोलसी में राहत प्रदान करने व कच्चे फायर कर्मचारियों को फायर ऑपरेटर पदों पर समायोजित करने व अन्य प्रमुख मांगों पर सरकार अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आगामी दिनों में कर्मचारी नगर निगम, पालिकाओं और जिला परिषद चुनावों के दौरान जनता के बीच हैंडबिल बांटकर सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। यूनियन नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन अब केवल दो कर्मचारियों को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे दमकल विभाग के अधिकारों, सुरक्षा और भविष्य का मुद्दा बन चुका है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा भी इस आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है।
इधर, भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं।
ऐसे में दमकल कर्मियों की हड़ताल से आपात सेवाएं प्रभावित होने की आशंका गहराने लगी है, जिससे आमजन की जान-माल को खतरा बढ़ सकता है।सरकार और यूनियन के बीच अब तक तीन दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार बार-बार आश्वासन तो दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, जिससे कर्मचारियों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान जोत सिंह,सचिव सोमनाथ, अशोक वर्मा,गुरनाम सिंह,एसकेएस जिला उपप्रधान प्रेम प्रकाश,सीटू नेता विनोद त्यागी,मीनाक्षी शर्मा व अन्य नेताओं ने अपना समर्थन दिया।हड़ताल स्थल पर ललित कुमार,वीरेंद्र धीमान,तेजिंदर सिंह,जगविंदर सिंह,तरसेम चँद,परवीन,अनिल चौहान, राजीव काम्बोज, प्रितमपाल, इंतजार अली,अंकित गुर्जर व अन्य उपस्थित रहें।

हरनोली चौकी पुलिस द्वारा 2 ग्राम स्मैक सहित आरोपी काबू

प्रमोद भार्गव,
गुहला चीका। जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चौकी हरनोली पुलिस की टीम ने एक आरोपी को 2 ग्राम स्मैक सहित काबू किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चौकी हरनोली प्रभारी एएसआई राजेश कुमार टीम के साथ गश्त व अपराध रोकथाम के लिए घघर पुल बाऊपुर डंडोता के पास मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस टीम को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गांव बलबेहड़ा पंजाब निवासी रवि कुमार जो बाइक पर सवार होकर गांव डंडौता की तरफ से गांव बाउपुर की तरफ आएगा, जिसके पास नाजायज असला है, जिसको घघर पुल बाऊपुर डंडोता के पास नाकाबंदी करके नाजायज असला सहित काबू किया जा सकता है। सूचना को पुख्ता मानते हुए पुलिस टीम ने तुरंत रेडिंग पार्टी गठित की और घघर पुल बाऊपुर डंडोता पर नाकाबंदी करके कुछ समय बाद

गांव डडौंता की तरफ से आए संदिग्ध बाइक सवार को काबू कर लिया गया। जिसकी पहचान उपरोक्त गांव बलबेहड़ा पंजाब निवासी रवि कुमार के रूप में हुई। जांच दौरान आरोपी के पेंट की जेब से एक प्लास्टिक पन्नी से 2 ग्राम चिट्टा(स्मैक) बरामद हुई। जिस बारे थाना चीका में मामला दर्ज मौके पर पहुंचे एएसआई जसबीर सिंह द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा।

न्यूज फ्लैश

बायोमैट्रिक व पोर्टल पर ट्रेक्टर की फोटो ये बंद हो: निर्भय रतिया

टीम एक्शन इंडिया
डॉ नैब सिंह मंडेर
रतिया 20 अप्रैल :
संयुक्त किसान मोर्चा, हरियाणा की ओर से आज मार्किट कमेटी सचिव, रतिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसानों ने गेहूँ खरीद प्रक्रिया में आ रही गंभीर समस्याओं को उठाया।
किसानों ने बताया कि वर्तमान में गेहूँ बेचने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और ट्रैक्टर की नंबर प्लेट सहित फोटो पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। पीक सीजन के दौरान पोर्टल बार-बार बंद हो जाता है या एरर दिखाता है, जिससे किसान अपनी फसल समय पर नहीं बेच पा रहे हैं और मंडियों में घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की कि इन अव्यवहारिक शर्तों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ताकि किसानों को फसल बेचने में आसानी हो सके। इसके साथ ही सरकार से यह भी मांग की गई कि सभी किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी सुनिश्चित की जाए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसान आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। इस मौके पर प्रमुख रूप से जिला प्रधान निर्भय (भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा), तेजिंदर सिंह थिंद (जम्हूरी किसान सभा), राजेंद्र बद्दू (किसान सभा जिला प्रधान) सहित किसान नेता कर्मा सिंह, गुरसेवक सिंह, रिशपाल सिंह, शेर सिंह और गगन भुल्लर उपस्थित रहे।

महमुदपुर चौकी पुलिस द्वारा 20 बोतल हथकढी शराब सहित आरोपी काबू

प्रमोद भार्गव,
गुहला चीका। अवैध शराब तस्करों व अवैध शराब खुर्दों पर एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के आदेशानुसार जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए आरोपी को 20 बोतल हथकढी शराब सहित काबू कर लिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चौकी महमुदपुर पुलिस के एएसआई लखविंदर सिंह की टीम द्वारा गश्त दौरान एक गुप्त सूचना मिलने उपरांत गांव खम्बेड़ा निवासी मुख्तयार सिंह के मकान पर दबिश देकर उपरोक्त आरोपी मुख्तयार सिंह को काबू कर लिया गया। जांच दौरान आरोपी के कब्जे में प्लास्टिक ड्रम से 20 बोतल हथकढी शराब बरामद हुई। जिस बारे थाना गुहला में मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

दुपहिया वाहन चोरी के मामले में दो आरोपी काबू

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस
करनाल। जिला पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी ऑटो व्हीकल थेफ्ट स्टाफ की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। यह कार्रवाई एंटी ऑटो व्हीकल थेफ्ट स्टाफ इंचार्ज उप निरीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में तथा सहायक उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा की गई। टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मोनू पुत्र रमेश निवासी गांव गौसाई खेड़ा थाना जुलाना जिला जीन्द तथा सोहनलाल उर्फ सोनू पुत्र सहीराम निवासी गांव माण्डी कलाँ थाना ऊचाना जिला जीन्द को मुनक रोड असंध से काबू किया। दोनों आरोपियो के कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों को थाना असन्ध में दर्ज चोरी के दो मामलों में गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने एक अन्य मुकदमा थाना शहर करनाल का भी खुलासा किया है।

समाज सेवा प्रत्येक व्यक्ति का आत्मिक फर्ज है: आयुक्त

डॉ नैब सिंह मंडेर
रतिया, 20अप्रैल :
रतिया उपमंडल के गांव लांबा में हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी के पहुंचने पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया
गांव लांबा में चहल निवास पर प्रमुख समाजसेवी एवं एनआरआई भूपेंद्र सिंह चहल (रूबन) के नेतृत्व में क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने पुष्पगुच्छ व फूलमालाएं पहनाकर आयुक्त कर्मवीर सैनी का स्वागत किया गया
लोक चेतना मंच हरियाणा के चेयरमैन डॉ नैब सिंह मंडेर ने स्वागत करते हुए बताया कि सम्मानित शख्सियत श्री कर्मवीर सैनी समाज सेवा को समर्पित

शख्ससियत हैं जनप्रतिनिधि के रूप में समाजसेवा में तीस वर्षो से बहुत बड़ी सेवा का दायत्व संभाला हुआ है कॉनफेड के चेयरमैन के रूप में भी पूरे हरियाणा में प्रशंसायोग सेवा है अब हरियाणा सरकार द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के पद पर बड़ी सेवा सम्मानयोग्य है
इस अवसर पर मुख्य सम्मानित शख्सियत श्री सैनी ने अपने सम्बोधन में कहा कि रतिया क्षेत्र में चहल निवास पर पहले भी कई वार आए है उन्होंने कहा कि रतिया क्षेत्र के लोग मन के अच्छे व जागरूक लोग हैं।
उन्होंने कहा कि समाज सेवा करना व दूसरों की मदद करना मनुष्य का फर्ज है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को समर्पित भावना के साथ अपना दायित्व निभाना चाहिए उन्होंने कहा जब से वह हरियाणा के सूचना आयुक्त बने हैं तब से आरटीआई के मामलों के अंदर आमजन की आवाज के मुताबिक मामले निपटाऐ जाने का कार्य बहुत ही सरल और उत्तमता के साथ किया जा रहा है।

अवैध देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस सहित एक संगठित गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार

नितिन सिंगला जगाधरी
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने जिला पुलिस को अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए हुए हैं। इन्हीं निदेर्शों के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा - 2 पुलिस टीम ने गांव पाबनी खुर्द के पास से एक युवक को लोडेड देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक एक संगठित गिरोह का सदस्य है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक

हिरासत में भेज दिया गया। इंचार्ज राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियार के साथ पाबनी खुर्द के पास संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा है। इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने तुरंत मौका पर पहुंचकर वहां संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे युवक को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से अवैध देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान गांव बाल छप्पर निवासी मनोज कुमार उर्फ अंकित पुत्र मदन लाल के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की जेल

जींद। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त एवं सत्र न्यायधीश शिफा कि अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में दोषी को पांच वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता राजेश ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि चार अप्रैल 2024 को थाना सदर सफीदों में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें पीड़ित की नाबालिग पुत्री को गांव ऐंचराखुर्द निवासी गौरव बहला फुसला कर ले गया था। पीड़िता के अभिभावक की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता से मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

रादौर मंडी में किसानों का हल्ला बोल, नए खरीद नियम वापस लेने की मांग

नितिन सिंगला जगाधरी
यमुनानगर)। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रादौर अनाज मंडी में किसानों ने नए फसल खरीद नियमों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला प्रधान सुभाष गुर्जर और अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के जिला प्रधान जरनैल सिंह सांगवान की अध्यक्षता में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय का करीब 3 घंटे तक घेराव किया।
किसान नेताओं महिपाल चमरौड़ी और दीप राणा ने कहा कि सरकार की नई खरीद नीति मंडियों को कमजोर करने और किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के जाल में उलझाने की साजिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इन नियमों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।किसानों ने आरोप लगाया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया में अत्यधिक समय लग रहा है, जिससे गेट पास बनने में देरी हो रही है और मंडियों में आवक के मुकाबले खरीद काफी कम है। वहीं, नमी का बहाना बनाकर फसल खरीद को टाला जा

जोरदार प्रदर्शन

किसान नेताओं ने केंद्र सरकार की नई कृषि विपणन नीति (एनपीएफएएम) पर भी सवाल उठाए

रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बेमौसमी बारिश से गेहूं को नुकसान से बचाने के लिए मंडियों में न तो पर्याप्त शेड हैं और न ही तिरपाल की व्यवस्था। उठान कार्य धीमा होने के कारण किसानों को भुगतान भी समय पर नहीं मिल रहा है।किसानों ने सरकार से मांग की कि नए नियमों को रद्द कर पुराने सिस्टम से ही खरीद की जाए। साथ ही, बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए गेहूं पर 500 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने और नमी की मात्रा को मौसम के अनुसार निर्धारित करने की मांग भी उठाई गई। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने केंद्र सरकार की नई कृषि विपणन नीति (एनपीएफएएम) पर भी सवाल उठाए।

एसडीएम को रतिया शहर की समस्याओं से अवगत करवाया

टीम एक्शन इंडिया
डॉ नैब सिंह मंडेर
रतिया, 20 अप्रैल :विधानसभा रतिया के एमिनेंट पर्सन सीएम विंडो सुनील इन्दौरा,उदय सिंह नम्बरदार, अन्जु जग्गा ने एस डी एम सुरेंद्र सिंह को मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि शहर की अनेकों समस्या जनता के माध्यम से मिल रही है जिसका निवारण बहुत जरूरी है क्योंकि कि हम नहीं चाहते कि जनता का विश्वास सरकार के प्रति टुटे ओर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली और कार्यप्रणाली दोनों ही जनता को समर्पित है। इसलिए

रतिया की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनका कठोरता से पालन व निवारण करवाएं उन्होंने निम्नलिखित अनुसार मांग रखी :
1. हाल ही में बने शहर में बने बरसाती पानी के खाले को साफ करवाया जाए ताकि बारिश के मौसम से पहले इसमें जमा गंदगी ओर मिट्टी निकाली जा सके।
2. शहर में मुख्य मैन बाजार सहित अन्य स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय बनवाएं जाएं ताकि लोगों को इसकी समस्याओं से निजात मिल सके।
3. शहर के गुगल मैप पोर्टल पर नक्शे में अनेकों कॉलोनियों का सही नाम ना होकर हरिजन बस्ती लिखा हुआ है जो संविधान ओर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित है इसे तुरंत प्रभाव से हटवाया जाए।
4. शहर में घरों के आगे बड़े बड़े रेम्प बने हुए हैं और लोगों ने इसकी शिकायत सीएम विंडो पर भी की हुई है जो वास्तविक है और रेम्पों को हटवाया जाए।
5. शहर में साफ सफाई का ध्यान रखते हुए सभी दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि वे अपना कुड़ा करकट अपने डस्टबिन लगाकर उसमें ही डालें और कुड़े उठान वाली गाड़ी आने पर उसमें डालें सड़क पर कुड़ा किसी भी समय ना डालने के निर्देश दिए जाएं।

गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल चीका में निबंध एवं कविता प्रतियोगिता का आयोजन

प्रमोद भार्गव,
गुहला चीका। गवर्नमेंट माडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल चीका द्वारा इको क्लब फार मिशन लाइफ की गतिविधियों के अंतर्गत वर्ल्ड अर्थ डे सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज यहां विद्यालय में निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कक्षा छह से कक्षा बारह तक के लगभग साठ विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, पृथ्वी बचाओ और सतत विकास जैसे विषयों पर अपनी लेखनी के

माध्यम से उम्दा प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निबंध और कविताओं में बच्चों ने पृथ्वी को बचाने के लिए अपने विचार और सुझाव बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। इस अवसर पर इको क्लब के प्रभारी लक्ष्मी नारायण ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने अर्थ डे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पृथ्वी हमारा घर है और इसे सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बच्चों को जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्लास्टिक का कम उपयोग, ऊर्जा की बचत और कचरा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के बारे में विस्तार से समझाया।

बिलासपुर में 27 एकड़ में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर

नोटिस के बावजूद नहीं मानी चेतावनी, सड़कों, प्लॉटिंग और बिजली ढांचे को किया ध्वस्त

नितिन सिंगला जगाधरी
यमुनानगर जिले के बिलासपुर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़े स्तर पर तोड़फोड़ अभियान चलाया। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) राजेश कुमार के अनुसार नियंत्रित क्षेत्र व्यासपुर में स्थित मौजा व्यासपुर में गणपति कॉलेज के पीछे, बिलासपुर-छछरौली रोड पर दो अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। प्रशासन की टीम ने करीब 27 एकड़ में फैली इन कॉलोनियों में बनाई गई कच्ची सड़कों, नींव, सीवरेज नेटवर्क, प्लॉटों की निशानदेही और बिजली के खंभों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
यह कार्रवाई उपायुक्त प्रीति के आदेशों के तहत की गई। मौके पर जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता राहुल और सागर, यूएचबीवीएन के एसडीओ राम कुमार (ड्यूटी मजिस्ट्रेट), थाना प्रभारी और राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की

टीम मौजूद रही, जिन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखी। डीटीपी राजेश कुमार ने बताया कि संबंधित लोगों को अर्बन एरिया एक्ट 1963 के तहत पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने विभागीय आदेशों की अवहेलना की। बिना अनुमति के कॉलोनी विकसित करने पर यह कार्रवाई की गई।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले पूरी जांच करें। अवैध निर्माण या खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ACTION INDIA

एक्शन इंडिया

Front Page - 2

एक्शन इंडिया ▸ नई दिल्ली ▸ 21 अप्रैल 2026 ▸ पृष्ठ 12 ▸ आरएनआईः DELHIN / 2006 / 19302

RKB GROUP
Rakesh Bhardwaj Group

प्रकृति और स्थानीय जीवन के कल्याण प्रयासों में ही सेवा की सार्थकता : राज्यपाल पटेल

टीम एक्शन इंडिया

भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि भारतीय वन सेवा, महज प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि मानवता, प्रकृति, वन्य जीव, सांस्कृतिक धरोहर और भावी पीढ़ियों के प्रति भी एक उत्तरदायित्व है। राज्यपाल पटेल सोमवार को भारतीय वन सेवा के 2024-26 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के सौजन्य भेंट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा में चयन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। लोकभवन के बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे। राज्यपाल पटेल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी सौभाग्यशाली है, जिन्हें जीवन भर प्रकृति की गोद में रहकर उसके संरक्षण और संवर्धन का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारी, वन कानूनों और जनजातीय कल्याण के प्रावधानों का गहनता से अध्ययन करें, उन्हें समझे और स्थानीय

आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करें। प्रशिक्षण की सीख को प्रकृति, वन, वन्य जीव और स्थानीय जन जीवन की बेहतरी में उपयोग करें। उनके कल्याण प्रयासों में ही आपकी सेवा की सार्थकता है। यह याद रखें कि आपका आत्मीय व्यवहार, वंचितों के प्रति समानुभूति और संवेदनशीलता ही आपकी सफलता का अंतिम पैमाना होगी।

समाधान

वनों की अवैधानिक कटाई, शिकार आदि समस्याओं के समाधान में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करें

पर्यावरण संरक्षण के लिए सोच, संकल्प और सेवा भाव जरूरी

राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्राकृतिक असंतुलन, पर्यावरणीय चुनौतियों आदि के कारण वन एवं वन्य जीवन के संकट का समाधान अत्यंत जरूरी है। वन अधिकारी के रूप में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन आपका प्राथमिक दायित्व है। इसके लिए आपकी सोच, संकल्प और सेवा का भाव सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के साथ हमेशा आत्मीय, सरल और सहज व्यवहार करें। अपने अच्छे व्यवहार और सहयोग से उनका विश्वास जीते। वनों की अवैधानिक कटाई, शिकार आदि समस्याओं के समाधान में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करें। राज्यपाल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक पेड़-माँ के नाम अभियान की चर्चा की। इसे स्थानीय सहभागिता से प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की सराहनीय पहल बताया।

जनसेवा सरकार का कर्तव्य, इसी पथ पर चल रही सरकार : मुख्यमंत्री योगी

टीम एक्शन इंडिया

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' में प्रदेश भर से आए फरियादियों से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा के अंदर निस्तारण कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा सरकार का कर्तव्य है और सरकार अपने कर्तव्य पथ पर चलकर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा कर रही है। हर उचित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार संकल्पित है। बरेली की रहने वालीं दीप्ति 'जनता दर्शन' में पहुंचीं। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपना दर्द बयां किया। पीड़ित ने बताया कि वह किराए के मकान में रहती है और ठेला लगाकर जीवनयापन कर रही है। आर्थिक विपन्नता के कारण बच्चों के लालन-पालन में काफी परेशानी हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने बरेली

के जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि महिला की समस्या सुनकर पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिलाते हुए स्थानीय स्तर पर समस्या का त्वरित समाधान कराएं। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को देखकर दीप्ति की आंखें भर आईं। चेहरे पर खुशी का भाव लिए हुए उन्होंने जाते-जाते मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और उन्हें ढेर सारी

समस्याएं

मुख्यमंत्री योगी ने को 'जनता दर्शन' में एक-एक फरियादी से मिलकर सुनीं समस्याएं

दुआएं भी दीं। 'जनता दर्शन' में कुछ लोगों ने आवास की मांग से संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने उनकी बातें सुनते हुए आश्वस्त किया कि सरकार हर पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करा रही है। योगी ने संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को आवेदकों का पत्र भेजते हुए उन्हें निर्देशित किया कि पात्रता के आधार पर इन्हें भी आवास योजना का लाभ दिलाएं। इन लोगों ने भी मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। मुख्यमंत्री के पास कुछ लोगों ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने तत्काल एस्टिमेट बनवाकर शासन को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि आप परिजन की चिंता कीजिए, इलाज की चिंता सरकार करेगी। वहीं कुछ अभिभावकों ने आर्थिक परेशानी का जिक्र करते हुए बच्चों की पढ़ाई पर चिंता जताई। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी बच्चे का स्कूल नहीं छूटना चाहिए। बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, वहीं उनकी शिक्षा जारी रहे, इसके लिए प्रबंधन से वार्ता कर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने अवैध कब्जे और पुलिस से जुड़े मामलों में लापरवाही का संज्ञान लेते हुए इन प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई कराने का निर्देश दिया और कहा कि स्थानीय पुलिस-प्रशासन समस्या का समाधान कराकर पीड़ितों को संतुष्ट करे।

डॉ. यादव ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बृजमोहन मिश्रा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की

अनुकरणीय

विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व संभाला। उनका यह कार्यकाल प्रेरणास्पद और अनुकरणीय रहा

टीम एक्शन इंडिया

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. बृजमोहन मिश्रा की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री तथा स्व. बृजमोहन मिश्रा की सुपुत्री अर्चना चिटनीस इस अवसर पर उपस्थित थीं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निमाड़ अंचल के सक्रिय और लोकप्रिय जननेता रहे बृजमोहन मिश्रा तीन बार विधानसभा सदस्य रहे। उन्होंने मार्च 1990 से दिसम्बर 1993 तक विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व संभाला। उनका यह

कार्यकाल प्रेरणास्पद और अनुकरणीय रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. मिश्रा की विद्यार्थी परिषद में सक्रियता का भी स्मरण किया। गौरतलब है कि 20 अप्रैल 1934 को वृन्दावन में जन्मे स्व. बृजमोहन मिश्रा का सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन विद्यार्थी काल से ही सक्रिय रहा। वर्ष 1947 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध का विरोध करने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वे विद्यार्थी राजनीति से सक्रिय होकर जनसंघ से जुड़े और 1972 में पहली बार विधायक बने। आपातकाल (1975-77) के दौरान मीसा के अंतर्गत निरुद्ध रहे और कठोर कारावास सहा। 1977 में पुनः विधायक चुने गए तथा विभिन्न समितियों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। 1980 में वनमंत्री के रूप में कार्य किया। 1990 में तीसरी बार विधायक निर्वाचित होकर 20 मार्च 1990 से 22 दिसंबर 1993 तक मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष रहे। 06 मई 2004 को उनका निधन हो गया।

चारधाम मार्गों के सुदृढ़ीकरण से यात्रा हुई अधिक सुरक्षित व सुगमः मुख्यमंत्री धामी

टीम एक्शन इंडिया

पौड़ी गढ़वाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में चारधाम यात्रा मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से यात्रा अब अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक हो गई है। यमकेश्वर स्थित वानप्रस्थ आश्रम में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बातें कही। उन्होंने श्रीमद्भागवत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह ग्रंथ मानव को धर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा देने के लिए विभिन्न

विकास पर बल

प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं

महत्वाकांक्षी परियोजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कालसी-हरीपुर क्षेत्र में यमुना तट पर घाट निर्माण, शारदा कॉरिडोर, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर और दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज की स्थापना जैसे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे प्रदेश की आर्थिकी और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिल रही है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक रेनू बिष्ट ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिली है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन में फरियादियों से संवाद कर सुनीं समस्याएं

टीम एक्शन इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने कैम्प कार्यालय सात कालिदास मार्ग पर आयोजित 'जनता दर्शन' में जन-सेवा और प्रशासनिक संवेदनशीलता की एक नई मिसाल पेश की। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि उप मुख्यमंत्री ने औपचारिकताओं को परे रखते हुए स्वयं एक-एक फरियादी के पास जाकर, उनसे सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याओं को अत्यंत आत्मीयता के साथ सुना। प्रदेश के विभिन्न सुदूर जनपदों से आए सैकड़ों फरियादियों ने अपनी पीड़ा साझा की, जिस पर श्री मौर्य ने न

केवल उन्हें ढांढस बंधाया, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर ही प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की। जनता दर्शन के दौरान बांदा जनपद से आए रामदत्त और ओम प्रकाश ने भूमि से दबंगों द्वारा किए गए अनाधिकार कब्जे को हटवाने की गुहार लगाई। वाराणसी

रूबरू

एक-एक फरियादी के पास जाकर, उनसे सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याओं को आत्मीयता के साथ सुना

से आए विजय शर्मा ने गंभीर बीमारी के उपचार के लिए चिकित्सा सहायता अनुदान और राजेंद्र कुमार ने जटिल भूमि विवाद के त्वरित निस्तारण का आग्रह किया। इसी क्रम में कानपुर देहात के दीपक कुमार ने अपने विरुद्ध दर्ज किए गए कथित फर्जी मुकदमे को निष्पक्ष जांच कर निरस्त कराने की अपील की, तो कासगंज के चंदन सिंह ने जमीन से जुड़े पुराने विवाद के न्यायसंगत निपटारे की मांग रखी। बदायूं जिले से आए फरियादियों की संख्या भी पर्याप्त रही, जिसमें राम विलास ने वैध विद्युत कनेक्शन होने के बावजूद दर्ज हुए मुकदमे की जांच कराने, चंद्रपाल ने बिजली संबंधी अन्य प्रकरणों और राम अवतार शाक्य ने अपनी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का पत्र दिया।

इसके साथ ही, बलरामपुर के राम अक्षयबर ने असाध्य रोग के इलाज के लिए आर्थिक मदद, फरुर्खाबाद की प्रेमवती शाक्य व सीतापुर के दीपू ने आवास दिलाने और महोबा के दयाशंकर ने अपनी पट्टे की जमीन को दबंगों के चंगुल से छुड़ाने की व्यथा सुनाई। इन तमाम प्रकरणों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने शासन की सक्रियता और संवेदनशीलता का परिचय दिया और कई जिलों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस कप्तानों से दूरभाष पर सीधी वार्ता की और निर्देश दिये कि धरातल पर पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक न्याय मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि चिकित्सा सहायता, आवास और अंत्योदय से जुड़े मानवीय मामलों में तत्काल प्रक्रिया पूरी कर राहत पहुंचाई जाए।

सिमराहा पुलिस ने भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप किया बरामद

अररिया। जिले की सिमराहा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डोरिया सोनापुर के थरिया बकिया गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने कोडीनयुक्त कफ सिरप की 100 एमएल की कुल 3443 बोतलें जब्त की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान थरिया बकिया निवासी मो. उमर के पुत्र आकिब तथा मो.जहागिर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के घर से

कफसिरफ के अलावे 66 हजार 50 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई का नेतृत्व सिमराहा थानाध्यक्ष प्रेम कुमार भारती ने किया। उनके साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है।

जल जीवन मिशन से ग्राम बंधी की बदली तस्वीर

तस्वीर बदल दी

जल जीवन मिशन ने ग्रामीणों की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का समाधान कर गांव की तस्वीर बदल दी

टीम एक्शन इंडिया

रायपुरः कबीरधाम जिले के विकासखंड सहसपुर लोहारा अंतर्गत ग्राम पंचायत बंधी में जल जीवन मिशन ने ग्रामीणों की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का समाधान कर गांव की तस्वीर बदल दी है। वर्षों से पेयजल

संकट से जूझ रहे इस गांव में अब हर घर तक नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंच रहा है। ग्राम सभा की सहमति से ग्राम बंधी को हर घर जल ग्राम घोषित किया गया है, जो गांव के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पहले ग्राम बंधी में गर्मी के मौसम के दौरान जल संकट गंभीर रूप ले लेता था। हैंडपंपों का जलस्तर नीचे चला जाता था और कई जल स्त्रोत सूख जाते थे। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को दूर-दराज के स्थानों से पानी लाना पड़ता था। पानी के लिए लंबी कतारें लगती थीं, जिससे घरेलू कामकाज और दैनिक दिनचर्या प्रभावित होती थी। कई बार खेती-किसानी और मजदूरी जैसे जरूरी कार्य भी बाधित होते थे। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत नलजल योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब ग्राम के प्रत्येक घर में नियमित जल आपूर्ति हो रही है। इससे ग्रामीणों को न केवल पेयजल संकट से राहत मिली है, बल्कि महिलाओं और बच्चों के समय और श्रम की भी बचत हो रही है। अब उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता, जिससे उनका जीवन अधिक सहज और व्यवस्थित हो गया है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना से बदली सेजाडीह की तस्वीर

टीम एक्शन इंडिया

रायपुर : प्रधानमंत्री जनमन योजना से कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में बसे ग्राम सेजाडीह की तस्वीर अब बदल चुकी है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से ग्राम सेजाडीह के लोगों को वह सुविधा मिली है जिसका इंतजार उन्होंने पीढ़ियों तक किया था। योजना के अंतर्गत पीएमजीएसवाई विभाग द्वारा सेंदूरखार से सेजाडीह तक 2.10 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण कराया गया है। इस सड़क निर्माण कार्य पर 1 करोड़ 56 लाख 88 हजार रुपए की लागत आई है। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि गांव पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। सड़क निर्माण के लिए

पहाड़ों की घाट कटिंग कर रास्ता तैयार किया गया। कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में बसे ग्राम सेजाडीह के लोगों के लिए एक समय ऐसा था, जब गांव तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। पहाड़ की ऊंचाई पर बसे इस गांव में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को वर्षों से आवागमन के लिए समस्या का सामना करना पड़ता था। गांव तक जाने के लिए केवल संकरे और पहाड़ी रास्ते थे, जिन पर पैदल चलना भी कठिन था। आजादी के दशकों बाद भी गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। मरीजों को अस्पताल ले जाना, बच्चों का स्कूल जाना, महिलाओं

सुविधाएं

ग्राम सेजाडीह के लोगों को वह सुविधा मिली है जिसका इंतजार उन्होंने पीढ़ियों तक किया था

का घरेलू सामान लाना, किसानों का उपज बाजार तक पहुंचाना हर काम कठिनाइयों से भरा हुआ था। ग्राम सेजाडीह के निवासी श्री धनसिंह धुर्वे बताते हैं कि पहले गांव तक कोई सड़क नहीं थी। राशन, दवाई, घरेलू सामान और खेती के लिए आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए पंडरिया और कुई बाजार तक जाना पड़ता था। सामान सिर पर या कंधे पर रखकर पहाड़ी रास्तों से गांव तक लाना बहुत कठिन था। धनसिंह कहते हैं कि अब पक्की सड़क बनने के बाद गांव तक वाहन आसानी से पहुंच रहे हैं। जरूरत का सामान सीधे गांव तक आ रहा है। इससे समय की बचत होने के साथ-साथ ग्रामीणों का श्रम भी कम हुआ है। अब गांव में हर मंगलवार को बाजार लगना भी शुरू हो गया है, जिससे लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों बाद उनके गांव तक विकास की सड़क पहुंची है।

प्लेसमेंट और एनबीए एक्रेडिटेशन पर सरकार का फोकसः उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी

टीम एक्शन इंडिया

पटना। बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के दृढ़ संकल्प के साथ उप मुख्यमंत्री - सह- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आज विभाग की एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्लेसमेंट और एनबीए एक्रेडिटेशन पर सरकार फोकस करेगी। राज्य के अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) महाविद्यालयों की रैंकिंग पर विशेष बल देते हुए उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय

स्थापित कर शिक्षा और आधारभूत संरचनाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि एनबीए जैसी संस्थाओं से एक्रेडिटेशन (मान्यता) प्राप्त करने की दिशा में 'मिशन मोड' में काम हो।